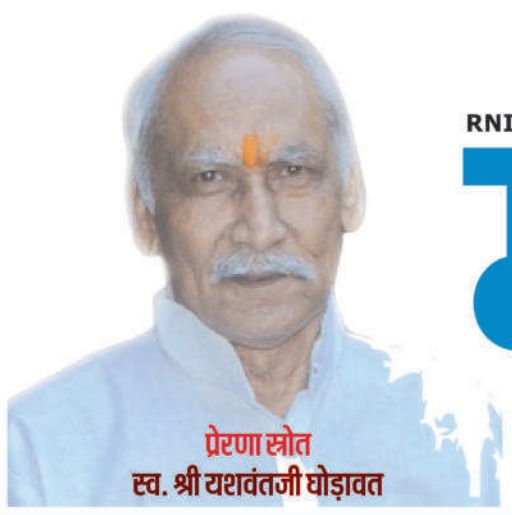
प्रेरणा स्रोत
स्व. श्री यशवंतजी घोड़ावत

RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ..सच

माही की गूंज

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

सुविचार

वे कहते है कूदने से पहले

दो बार सोचो। मैं कहता हूं पहले कूदो और फिर जितना चाहे उतना सोचो।

रजनीश 'ओशो'

वर्ष-05, अंक - 12 (साप्ताहिक) खवासा, गुरुवार 22 दिसम्बर 2022 पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

बिगड़े बोलः कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया का दरबारी कुत्ता-भाजपा विधायक शर्मा

भोपाल, एजेंसी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कही गई 'कुत्ता-चूहे' टिप्पणी पर बवाल मच गया है। वही अब मध्य प्रदेश में भाजपा नेता ने मर्यादा की सीमा लांघ दी। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने खड़गे पर पलटवार करते हुए उन्हें सोनिया गांधी का दरबारी कुत्ता कह डाला।

भाजपा विधायक श्री शर्मा

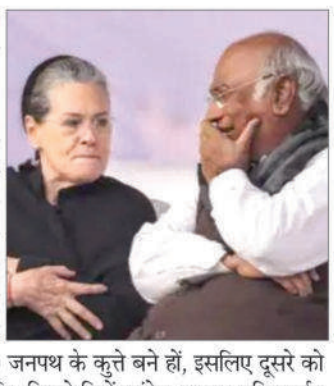

न्यूज एजेंसी से बातचीत में रामेश्वर ने कहा, क्योंकि कांग्रेस को कुत्ते गिनने की आदत हो गई, आदमी गिनने की आदत नहीं हुई। देशभक्तों के सम्मान की आदत नहीं हुई। ये जैसे सोनिया गांधी के दरबारी कुत्ते बने घूमते हैं, उसी दृष्टि से ये देखते हैं। जो खुद कुत्ता होता है वह दूसरों को कुत्तों की तरह देखता है। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे को समझना चाहिए खुद सोनिया गांधी के 10 जनपथ के कुत्ते बने हों, इसलिए दूसरे को कुत्ता कहना अपराध है। बता दे कि, पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान के अलवर में भाजपा पर निशाना साधते हुए पूछा कि, क्या आपके घर का कोई कुत्ता भी शहीद हुआ है...? खड़गे ने कहा, देश को हमने आजादी दिलाई है। देश की एकता के लिए इंदिरा गांधी व राजीव गांधी ने अपनी जान दी देश की एकता के लिए, यह सब हमने किया। हमारी पार्टी के नेताओं ने अपनी जान दी, तुमने क्या किया...? आपके घर में देश के लिए कुत्ता तक क्या मरा है...? क्या कोई कुर्बनी दी है...? नहीं, लेकिन फिर भी वो देशभक्त और हम कुछ बोलेंगे तो देशद्रोही। खड़गे के इस बयान पर भाजपा आगबबूला हो गई और संसद में उनसे माफी की मांग की।

टीएमसी सांसद पर भड़के शाह कहा ऐसा व्यवहार ठीक नहीं

नई दिल्ली। देश में नशे और ड्रग्स तस्करी पर लगाम कसने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में दी। इसी दौरान वह टीएमसी के सांसद सौगत रॉय की टोका-टोकी पर उखड़ भी गए। उन्होंने पहले तो सौगत रॉय से कहा कि, वह शांत रहें और मेरा भाषण समाप्त होने के बाद ही बात करें। इसके बाद भी सौगत रॉय लगातार बोलते रहे तो अमित शाह का गुस्सा और बढ़ गए। वह अपनी सीट पर ही बैठ गए और कहा कि, दादा पहले आप बोल लीजिए। यही नहीं उन्होंने कहा कि इस तरह का व्यवहार आपकी उम्र और कद के लिहाज से ठीक नहीं है।

इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दखल दिया और सांसद सौगत रॉय से शांत रहने की अपील की। इसके बाद अमित शाह फिर से खड़े हुए और अपने भाषण को आगे बढ़ाया। सौगत रॉय टीएमसी के वरिष्ठ सांसद हैं और मनमोहन सिंह सरकार में वह शहरी विकास राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। अमित शाह के भाषण के दौरान वह क्या बोल रहे थे, यह तो नहीं सुना जा सकता, लेकिन गृह मंत्री उनकी ओर से आए व्यवधान से नाराज हो गए। अमित शाह ने कई बार उन्हें चुप रहने की सलाह दी और लगातार व्यवधान के बाद बैठ ही गए। अमित शाह ने कहा कि, नशा हमारे देश में पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा है। नशे के कारोबार से होने वाली कमाई आतंकवाद को बढ़ावा देने में लगती है। इसलिए नशे पर लगाम कसकर हम एक साथ दो मोर्चों पर सफलता पा सकते हैं। होम मिनिस्टर ने कहा कि, तमाम दलों के बीच अकसर कई मुद्दों पर मतभेद रहे हैं, लेकिन आतंकवाद से निपटने में सभी राज्य केंद्र के साथ मिलकर चले हैं। हमारी सरकार ने बीते तीन वर्षों में कई सारी व्यवस्थाएं की हैं। सबसे बड़ा बदलाव यह किया है कि हम किसी भी जांच को अलग से नहीं देख सकते।

मंत्री जी जनता के बीच जाए न कि कोर्ट में...

माही की गूंज, संजय भटेवरा

झाबुआ। वैसे तो न्यायालय में अपनी बात रखने का अधिकार सभी को है। लेकिन लोकतंत्र में मुख्य भूमिका आम जनता की रहती है। आम जनता ही राजा को रंक और रंक को राजा बनाती है। यह आमजनता की ताकत ही है की वह आपको अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर पहुंचा सकती है। लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधि को अगर लगता है कि, उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो जनता के बीच जाए न कि कोर्ट में।

क्या है मामला

विगत दिनों बदनावर के होटल में हुई घटना का है, जिसमें एक युवती पहचान पत्र मांगने पर भड़क जाती है और प्रदेश के उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करती है। जिसका वीडियो वायरल हो जाता है। हालांकि बाद में लड़की की तरफ से एक वीडियो जारी किया जाता है जिसमें वो घटना से इंकार करती है और वीडियो जारी करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को कहती है। उसके बाद कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बदनावर की होटल में तोड़फोड़ कर दी जाती है। पूरी घटना को लेकर मामले की असलियत को मंत्री जी को आम जनता के सामने रखा जाना था। लेकिन मंत्री जी मीडिया के खिलाफ कोर्ट में पहुंच जाते हैं और अपनी छवि का हवाला देकर मीडिया में वो खबरें न चलाने की कोर्ट में गुहार करते हैं। लेकिन कोर्ट द्वारा इंकार कर दिया जाता है और कहा जाता है कि, आप मानहानि का दावा दर्ज करवा सकते हैं।

मंत्री जी अपने क्षेत्र की जनता को सफाई दे

मामला प्रदेश के कैबिनेट मंत्री से जुड़ा होने के कारण मंत्री जी को न केवल अपने क्षेत्र की जनता वरन् प्रदेश की जनता के सामने आकर अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए कि, वे क्या लड़की को जानते हैं...? यदि नहीं जानते तो लड़की ने मंत्री जी के नाम का उपयोग क्यों किया...? सोशल साइट पर मंत्री जी के साथ लड़की के फोटो फर्जी है...? अगर लड़की ने कुछ गलत किया है तो मंत्री जी को लड़की के खिलाफ केस दर्ज करवाना चाहिए न की मीडिया के खिलाफ कोर्ट में गुहार लगानी जानी चाहिए। यही नहीं होटल में तोड़फोड़ करने वाले के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। यही नहीं अगर उस लड़की को लगता है कि, वायरल वीडियो फर्जी है तो उसको अपने कथन अनुसार वीडियो जारी करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करना ही चाहिए।

कुल मिलाकर पूरे घटनाक्रम के बाद यह तो तय है कि, आम जनता में मंत्री जी की छवि धूमिल हुई है और आम जनता में धूमिल हुई छवि को आम जनता के बीच में जाकर ही सुधारा जा सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि, मंत्री जी आम जनता के सामने ही पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा रखें और दूध का दूध और पानी का पानी करें।

होटल में मंत्री जी उर्फ राजा साहब राजवर्धन सिंह के लिए किस तरह से युवती ने अपने शब्दो का प्रयोग किया। देखे क्युआर कोड स्क्रेन कर माही की गूंज यूट्यूब चैनल पर प्रकाशित समाचार।

पंजाब सीमा पर मार गिराया पाकिस्तानी ड्रोन

अमृतसर, एजेंसी। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों ने अंतरराष्ट्रीय सीमा के रास्ते पंजाब में घुसने वाले एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि, ड्रोन पाकिस्तानी सीमा में जा गिरा। अधिकारी के मुताबिक, बीएसएफ जवानों ने मंगलवार रात 7 बजकर 20 मिनट पर एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया।

उन्होंने बताया कि, घटना अमृतसर में दाओके पुलिस चौकी के पास हुई। बीएसएफ के एक प्रवक्ता ने बताया कि, बुधवार सुबह जब तलाशी ली गई तो ड्रोन भारतीय सीमा चौकी भरोपाल के उस पार पाकिस्तान की सीमा में 20 मीटर अंदर गिरा पाया गया। बाद में पाकिस्तान रेंजर्स उसे अपने साथ ले गए। प्रवक्ता के अनुसार, ड्रोन रोधी उपाय किए जाने के बाद वह (ड्रोन) कुछ मिनटों तक आसमान में उड़ा और फिर लौटते समय जमीन पर गिर गया। ड्रोन के जरिये भारतीय सीमा में कुछ गिराया तो नहीं गया है, इसका पता लगाने के लिए जांच जारी है।

प्रवक्ता के मुताबिक, पंजाब में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ही मादक पदार्थों की बरामदगी की भी एक घटना सामने आई है। हालांकि, यह घटना ड्रोन विमान से संबंधित नहीं है। बीएसएफ ने मंगलवार देर रात दो बजे के आसपास फजिल्का जिले के एक खेत से 25 किलोग्राम संदिग्ध हेरोइन बरामद की।

प्रवक्ता के अनुसार, फजिल्का जिले के गट्टी अजायब सिंह गांव के पास भारत-पाकिस्तान सीमा पर बाड़ के दोनों ओर कुछ संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद जवानों को सतर्क कर दिया गया। बीएसएफ के जवानों ने सीमा पर लगी बाड़ के पास पाकिस्तानी तस्करों पर गोलीबारी की। हालांकि, तस्कर घने कोहरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। प्रवक्ता ने बताया, घटना में लगभग 25 किलोग्राम के वजन के 25 पैकेट बरामद हुए हैं, जिनमें हेरोइन भरे होने का संदेह है। एक पीवीसी पाइप और एक शॉल भी बरामद की गई है।

एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेकिंग हुई आसान

नई दिल्ली, एजेंसी। जल्द ही आपको देश के हवाईअड्डों पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने बैग से निकालने की जरूरत नहीं होगी। विमानन सुरक्षा की निगरानी करने वाली संस्था बीसीएएस ने हवाईअड्डों पर कंप्यूटर टोमोग्राफी तकनीक पर आधारित स्कैनर लगाने की सिफारिश की है। इस तकनीक पर आधारित स्कैनर इंस्टॉल होने के बाद आपको अपने सामान से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निकालने की जरूरत नहीं होगी। मौजूदा वक्त में हवाईअड्डों पर इस्तेमाल किए जाने वाले स्कैनर हैंड बैगेज के अंदर की चीजों की द्वि-आयामी तस्वीर दिखाता है।

नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) के संयुक्त महानिदेशक जयदीप प्रसाद ने बुधवार को कहा कि, नियामक ने हवाई अड्डों पर कंप्यूटर टोमोग्राफी तकनीक पर आधारित स्कैनर स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है जो हाथ के सामान में वस्तुओं का त्रि-आयामी दृश्य प्रदान करेगा। उन्होंने कहा, इस तरह के स्कैनर से यात्रियों को स्कैनर से गुजरने से पहले अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को हैंड बैगेज से बाहर निकालने की जरूरत नहीं होगी। इस तरह के स्कैनर लगाने से हवाईअड्डों पर सुरक्षा जांच की प्रक्रिया में तेजी लाने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।

तवांग में बेहतर होगी मोबाइल कनेक्टिविटी

ईटानगर, एजेंसी। अरुणाचाल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प के बाद सरकार कई कदम उठा रही है। तवांग जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि, अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के पास कनेक्टिविटी में सुधार के लिए सरकार ने और मोबाइल टावर लगाने का फैसला किया है। ये फैसला 9 दिसंबर को यांग्त्से में भारत-चीन संघर्ष के बाद हुआ है। तवांग के उपायुक्त केएन दामो ने कहा कि बीएसएनएल और भारती एयरटेल कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 23 नए मोबाइल टावर लगाएंगे।

केएन दामो ने कहा कि, मौजूदा टावरों से मनचाही सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं जिससे न केवल सुरक्षाबलों बल्कि सीमा पर रहने वाले नागरिकों के लिए भी समस्याएं पैदा हो रही थीं। उन्होंने कहा कि, पहले सीमावर्ती इलाकों में मोबाइल नेटवर्क नहीं था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है और बुम-ला और वाई-जंक्शन पर भी लोग इंटरनेट सेवा और मोबाइल कनेक्टिविटी का आनंद ले रहे हैं, लेकिन इसमें और सुधार की जरूरत है। दामो ने कहा कि, रक्षा प्रतिष्ठानों को प्राथमिकता दी गई है, जबकि मागो, चूना और निलिया (जेमिथांग के पास) जैसे नागरिक क्षेत्रों की भी उपेक्षा नहीं की गई है।

पूरी है तैयारी

तवांग के उपायुक्त केएन दामो ने कहा कि, जिला प्रशासन ने 43 नए टावर मांगे थे। अधिकारी ने कहा कि, नए टावर लगाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन सर्दी एक चुनौती होगी, जिससे प्रक्रिया में देरी हो सकती है। हालांकि, जिले के पहाड़ी इलाकों में हिमपात हो रहा है, मुख्यालय में रविवार रात पहली बार हिमपात हुआ और तापमान -3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया।

बायजूस खरीद रहा बच्चों के फोन नंबर, दे रहा माता-पिता को धमकी

नई दिल्ली। एडटेक कंपनी बायजूस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बायजूस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आयोग ने कहा कि, उन्हें जानकारी मिली है कि कंपनी की तरफ से बच्चों के फोन नंबर्स खरीद कर उनके माता-पिता को कोर्स खरीदने के लिए धमकी दी जा रही है।

एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने कहा कि हमें पता चला है कि बायूज बच्चों और उनके पेरेंट्स के फोन नंबर खरीद रही है और उन्हें धमकी दे रही है कि अगर उन्होंने कोर्स नहीं खरीदा तो उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा।

एनसीपीसीआर की चेयरपर्सन प्रियांक कानूनगो ने बताया कि, हमें पता चला कि कैसे बायजू बच्चों और उनके माता-पिता के फोन नंबर खरीदता है और उन्हें धमकी देता है कि उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। हम कार्रवाई शुरू करेंगे और जरूरत पड़ी तो रिपोर्ट बनाएंगे और सरकार को लिखेंगे।

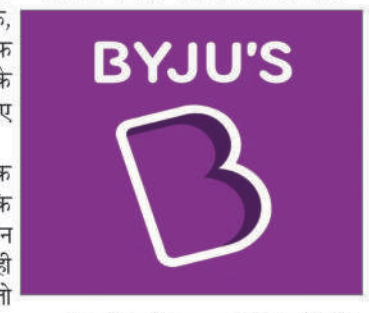

पिछले हफ्ते शुक्रवार को आयोग ने बायजू के सीईओ बायजू रवींद्रन को समन जारी कर 23 दिसंबर को छात्रों के लिए अपने पाठ्यक्रमों की हार्ड सेलिंग और अनुचित तरीके से बिक्री को लेकर व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है।

प्रियांक कानूनगो ने कहा कि, हाल ही में हमने एक रिपोर्ट पढ़ी, जिसमें बायजूस के काम करने का तरीका बिल्कुल भी नहीं बदला था, जिसके बाद हमने बायजूस के सीईओ को समन किया है और कमीशन के सामने 23 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा है, जिसके बाद हम आगे की कार्रवाई तय करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमने शिक्षा मंत्रालय, एसएफआईओ, आरबीआई को इस मामले के बारे में जानकारी दे दी है। उस वक्त एसएफआईओ ने जांच करने के लिए आरबीआई और कारपोरेट मंत्रालय को पत्र लिखा था। शिक्षा मंत्रालय ने भी एडटेक कंपनी के लिए विस्तृत सलाह जारी की थी और बायजूस को भी नोटिस जारी किया था।

चीन से आवागमन रोकने के साथ सीमा पर भी सावधानी जरूरी...

नई दिल्ली, एजेंसी। चीन में कोरोना इन दिनों तबाही मचा रहा है। जानकारों के मुताबिक अभी चीन में यह लहर थमने वाली नहीं है। चीन के अस्पताल मरीजों से पटे पड़े हैं। श्मशान में जगह नहीं रह गई है। 2019 में कोरोना महामारी की शुरुआत भी चीन से हुई थी। हालांकि कोरोना ने असली तबाही दूसरे देशों में मचाई थी। इस बार चीन से ही कोरोना का नया वेरिएंट फैलने लगा है। आपका बता दें कि, तीन वर्ष के बाद भी चीन और भारत के बीच डायरेक्ट विमान सेवा शुरू नहीं हो पाई है। हालांकि दूसरे देशों से आवागमन जारी है। इसी तरह 2020 में भी हुआ था। चीन से लोग भारी संख्या में इटली जाते थे। इटली में चीन के बाद कोरोना ने पैर पसारे और लाखों लोगों की मौत हो गई। इसके बाद दुनिया के देशों में कोरोना फैलना शुरू हुआ जिसने लोगों को पस्त कर दिया।

केंद्र ने की बैठक

चीन के हालात देखते हुए भारत सरकार ने भी एहतियात बरतने की सलाह दी है। बुधवार को केंद्र सरकार ने समीक्षा बैठक की और जरूरी उपाय करने के बारे में चर्चा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई बातों पर जोर देने को कहा गया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि, भारत किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। वहीं राज्यों से जीनोम सेक्वेंसिंग बढ़ाने को कहा गया है जिससे कि कोरोना के नए वेरिएंट की पहचान की जा सके।

क्या चीन से आवागमन और सीमा पर लगना चाहिए प्रतिबंध...?

पड़ोसी चीन में जिस तरह से कोरना तबाही मचा रहा है वह चिंता का विषय है। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी में ढील दिए जाने के बाद संक्रमण तेजी से फैला है। भारत की सीमा चीन से लगी हुई है। इसके अलावा भारत बड़ी मात्रा में चीन से आयात भी करता है। हालांकि आयात और निर्यात पर रोक नहीं लगाई जा सकती। भारत और चीन के बीच डायरेक्ट विमान सेवा अभी शुरू ही नहीं हुई है। कहा जा रहा था कि, मार्च 2023 से विमान सेवाएं शुरू की जाएंगी। हालांकि इसपर कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ था। हालांकि भारत को सबसे पहले एयरपोर्ट पर सावधानी बरतनी होगी। बाहर से आने वाले लोगों की जांच जरूरी है। एक अनुमान के मुताबिक अगले 90 दिनों में चीन की 60 फीसदी आबादी कोरोना संक्रमित हो जाएगी।

सच छिपाता चीन

चिंता की बात यह भी है कि चीन सच छिपाने में माहिर है। ऐसे में चीन में होने वाली मौतों और वायरस के रिस्क की सही जानकारी नहीं मिल पाती। चीन के वुहान से ही संक्रमण की शुरुआत हुई थी लेकिन चीन हमेशा इस बात से इनकार करता रहा। इसी तरह चीन जब कोरोना के कहर से जूझ रहा है तो वह दुनिया के सामने सही आंकड़े नहीं रख रहा है।

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में हाथ आजमाएगी भीम आर्मी

ग्वालियर। मध्य प्रदेश में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर अभी से सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। इन चुनावों को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। साथ ही उन दलों ने भी अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं जो अब तक सूबे में हुए चुनावों से दूर थे। सभी दलों के निशाने पर सूबे के अनुसूचित जाति और जनजाति मतदाता थे। भाजपा और कांग्रेस इन्हें लुभाने के लिए जोर-आजमाइश करते नजर आ रहे थे। अब भीम आर्मी ने भी सूबे के विधानसभा चुनाव में उतरने का ऐलान कर मुकाबले को रोचक बना दिया है।

चंद्रशेखर ने किया एलान

भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर मंगलवार को ग्वालियर पहुंचे थे, इस दौरान बड़ी संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। चंद्रशेखर बुधवार को यहां एक रैली को भी संबोधित किया। इस मौके पर चंद्रशेखर ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को पूरी ताकत से लड़ने का एलान किया। उन्होंने कहा, भीम आर्मी पूरी मजबूती के साथ सूबे में संगठन खड़ा करके आगामी विधानसभा चुनावों में भागीदारी करेगी और बहुजन समाज के मुद्दों को उठाएगी।

मूवी विवाद ध्यान भटकाने की साजिश

पठान मूवी के बेशरम रंग गाने में दीपिका पादुकोण के भगवा रंग की बिकनी पहन कर किए गए डांस को लेकर हिंदूवादी संगठनों के विरोध पर चंद्रशेखर ने कहा कि, बहुजन समाज को इन मुद्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह के मुद्दे समाज का ध्यान हटाने के लिए खड़े किए जाते हैं। इन मुद्दों का समाज से कोई सरोकार नहीं है। भीम आर्मी इस तरह के मुद्दों पर कोई स्टैंड नहीं लेती है।

सावधान : लच्छेदार बातों में उलझाकर की जा रही ठगी, ठगों का नया तरीका

अनजान लोगों के फोन कॉल से रहे सावधान वरना हो जाएगा बैंक खाता नील

माही की गूंज, पेटलावद।

सोशल मीडिया से जुड़े साइबर क्राइम को अंजाम देने वाले आये दिन ठगी के नए-नए तरीके ईजाद करते हैं, जिनके झांसे में आकर कई लोग शिकार हो चुके हैं। बढ़ती ठगी के मामलों के लोगो को तरीका पता चल जाता है तो ये ठग नया तरीका खोज कर फिर से लोगो को अपना निशाना बनाते हैं। गत दिनों ऐसे मामले सामने आये, जिंसमे अज्ञात व्यक्ति ने ठगी के शिकार लोगो को स्वयं का जान-पहचान का बता कर उनको उनके व्यवसाय से जुड़े सामान का आर्डर देकर उसका भुगतान करने के झांसे में लेकर ठगी की है। ऐसे मामले पेटलावद नगर सहित आसपास के क्षेत्र में तेज़ी से सामने आए हैं। जिनसे सावधान रहने की आवश्यकता है वरना आपके बैंक खाते में जमा राशि गायब हो जाएगी ।

नए तरीके से कुछ ऐसे हो रही है ठगी

ऐसा ही मामला बामनिया में सामने आया जहां एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा केक बनाने के नाम पर लड़की से ठगी की। व्यक्ति ने पहले केक का आर्डर किया ओर उसका भुगतान करने के लिये केश-लेश पेमेंट(ऑनलाइन) भुगतान किया और भुगतान नही होने पर ओटीपी देने को कहा जैसे ही लड़की ने ओटीपी दिए लड़की के खाते से 12 हजार रुपये उड़ गए। एक अजीब मामला ओर सामने आया जिंसमे ठग ने एक क्योसक संचालक को खुद को परिचित बताते हुए खाते में 20 हजार ट्रांसफर करने को कहा गया और पेमेंट अपने व्यक्ति को भेजकर करने की बात कही। दूसरी ओर उसी व्यक्ति ने एक होटल संचालक को 300 सौ कचौरी का आर्डर दिया और उसी के एडवांस राशि के भुगतान के लिए अज्ञात व्यक्ति ने उसी कियोस्क संचालक के पास भेजा जिसको बीस हजार खाते में डालने को कहा था । चालू फोन में होटल संचालक कियोस्क वाले के पास पहुँच जाता है जहां कियोस्क संचालक से बात कर उसे कहता है कि, मैने पेमेंट भेजा है इस व्यक्ति के साथ मेरे खाते में पैसे डाल दो, अज्ञात ठग अपनी लच्छेदार बातों में कुछ ऐसा माहौल बनाता है कि, होटल संचालक से बात किये बिना खाते में अज्ञात के खाते में लगभग 13 हजार डाल देता है और फोन कटने के बाद होटल संचालक और क्योसक संचालक एक-दूसरे को भुगतान के लिए बोलते हैं तब जा कर समझ आता है कि, वो दोनों अज्ञात व्यक्ति के झांसे में आकर ठगी का शिकार हो चुके हैं। मामला पुलिस चौकी पर भी पहुचा जहा अज्ञात नम्बर से

आये फोन नम्बर सहित पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी गई। लेकिन साइबर क्राइम ओर ठगी को लेकर झाबुआ पुलिस आज तक कोई सफलता अर्जित नही कर पाई ।

पुराना परिचित होने का हवाला दे कर उलझते है ठग, सामने वाले को होती है पूरी जानकारी

नए तरह की ठगी करने वाले शातिर अपनी मीठी बातों में उलझते है, जिसको भी ये टारगेट बनाते हैं उनकी पूरी जानकारी इनके पास होती है। जिससे बात करते समय पहचान करने में परेशानी नही होती और सामने वाला न जानते हुए भी ठग को परिचित ही मान लेता है और अपनी परेशानी बताकर जैसा-जैसा वो चाहता है करवाकर अंत मे आपके खाते से राशि उड़ाकर ठगी कर लेता है। अज्ञात व्यक्ति सामने वाले का नाम लेकर बात करता है और पहचान होने की बात करता है जब व्यक्ति उसकी लच्छेदार बातों में आ जाता है तब खुद की परेशानी या किसी से पैसे लेने में समस्या आने पर भुगतान सामने वाले के खाते में डालने की बात करता, ठगी के शिकार होने वाले व्यक्ति को लगता है कोई परिचित ही होगा जो उनके खाते में पैसे डलवा रहा है और बाद में लेगा, यही से ठगों का खेल शुरू होता है। अज्ञात व्यक्ति भुगतान के लिए कई तरह की परेशानी बताकर सामने वाले के मोबाइल पर आई ओटीपी हासिल कर लेता है और इसके बात वही होता है जो होता आया है। खाते में राशि आने की बजाए खुद के खाते में रखी राशि भी उड़ जाती है। खबर के साथ क्यू आर कोड के माध्यम से आपको ठगी के लिए की गई बातचीत का पूरा ब्यौरा सुनवाते है जिंसमे सतर्क व्यक्ति ठगी का शिकार होने से बाल-बाल बच गया ।

पुलिस निष्क्रिय, सावधान रहने की सलाह देकर करती है इतिश्री

इस प्रकार की ठगी होना कोई नया नही है। आये दिन ये ठग नए-नए तरीके से लोगो को ठगी का निशाना बना रहे हैं। हजारो शिकायते पुलिस के पास आवेंदन के रूप में पहुँच चुकी हैं, लेकिन जिले की निष्क्रिय और साइबर क्राइम को ट्रेस करने में असफल पुलिस, शिकायतकर्ताओ को

क्युआर कोड स्केन कर सुने ठगोरे किस तरह से ठगने के नये-नये तरिके कर रहे निजात।

ऐसे मामलों में सावधान रहने की सलाह देकर इति श्री कर लेती हैं। जबकि इन ठगों के झांसे में पड़े लिखे ओर समझदार आ जाते हैं तो जिले की पृष्ठभूमि के अनुसार अनपढ़ ओर कम पढ़े लिखे जिनको मजबूरी में भी ऑनलाइन पेमेंट के मोबाइल एप चलाने पड़ रहे हैं। वो इन ठगों के आसनी से शिकार बन रहे। पुलिस को इस प्रकार के क्राइम को ट्रेस करने के लिए अलग से विशेष टीम बनाकर इन ठगों तक पहुँचना चाहिए ताकि ऐसे लोगो को पकड़े जाने का डर रहे।

मामा झूठ बोलता है...

सड़क पर धरना प्रदर्शन।

पीएचई विभाग को ज्ञापन देते हुए।

माही की गूंज, पारा।

विधायक वालसिंह मेड़ा पारा जल-जीवन मिशन के अंतर्गत धमोय पारा नल-जल योजना प्रारंभ करने के लिए विशाल जन आंदोलन कर ग्राम वासियों के साथ कांग्रेस का धरना प्रदर्शन किया गया। स्थानीय बस स्टेण्ड पर पेयजल समस्या से निजात दिलाने हेतु किये गए धरना प्रदर्षन में पारा व आस- पास क्षेत्र के सैकड़ों लोग शामिल हुए। पिछले कई वर्षो से पीने के पानी की समस्या से निजात दिलाने की मांग की जा रही है। परंतु प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज तक इस मांग को पूरी नहीं की। पानी के अलावा पारा व आस-पास क्षेत्र के कई समस्याओं से ग्रषित है। छोटे-बड़े सभी वर्ग के लोग वर्तमान दिनों में महंगाई की मार झेल रहे हैं। पानी, बिजली, दवाई, खाद की किल्लत से जनता परेशान है। कांग्रेस ने प्रदेश के मुख्यमंत्री व पीएचई विभाग को आड़े हाथों लेते हुए खुली चेतावनी देते हुए कहा कि, अगर 15 दिन से एक माह तक में इस समस्या की सुनवाई नहीं हुई तो आगे जाकर बड़ा जन आंदोलन कर प्रदेश की भाजपा सरकार का घेराव किया जाएगा।

बता दे कि, 4 जनवरी 2022 में 8 करोड़ 35 लाख 17 हजार रुपये स्वीकृत पेयजल की समस्या के समाधान के लिए मंजुर हुए। सरकार के नुमाइंदो ने उक्त कार्य का भूमि पूजन भी किया गया। लेकिन आज तक कार्य प्रारंभ नही किया गया। कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने अपने-अपने उद्बोधन दिए। सबसे पहले झाबुआ जिला कोषाध्यक्ष प्रकाश रांका ने कहा कि, जल ही जीवन है और जल से ही सभी कार्यो की शुरवात करते है। योजना के तहत 6 गांव को शामिल किया गया था। उसके बाद 11 गांव को और जोड़ते हुए अब लागत बड़ा कर 32 करोड़ 58 लाख की डीपीआर तैयार की गई थी, एवं स्वीकृति हेतु भोपाल भेजा गया था। आज 2 वर्ष बीत गए नल-जल योजना की मंजूरी आज तक नहीं हो पाई । नल-जल योजना के तहत ग्राम पारा, रातिमाली, बाकी, झुमका, पिथमपुर, धमोए, चुडेली, बराड, कालमोड़ा, सेमलखेड़ी, सागिया, तेजरिया, जसोदा हिरजी, पलसाड़ी, दतियाघाटी, गावलिया, बावड़ी इन 17 गावों को सम्मिलित किया गया है। इस योजना का भूमि पूजन प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के द्वारा किया गया था। भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि, प्रदेश की सरकार विभागो के कमीशन के चक्कर में पीएचई विभाग में मंजूर हुई योजना धूल खा रही है। नागरिकों को संबोधित करते हुए यह भी बताया कि, यह कार्यक्रम कोई कांग्रेस पार्टी का नही है और नहीं भाजपा का यह कार्यक्रम हम सभी के लिए हैं। रांका ने चेतावनी देते हुए कहा है की सुनवाई न होने पर कलेक्टर का घेराव किया जाएगा।

युवा मोर्चा प्रदेशध्यक्ष डा. विक्रांत भूरिया ने विभागो को फटकार लगाते हुए कहा, विभागो में बैठे भ्रष्ट कर्मचारियो ने अगर 17 गावों को पानी नहीं पहुचाया तो जबरजस्त जन आंदोलन करेंगे। पीएचई विभागो में बैठे भ्रष्ट लोग सभी भाजपा के है विभाग में बैठे भ्रष्ठो कान खोलकर सुन लो अब अगर कार्य नहीं हुआ तो जम कर तमाचा पड़ेगा। हम लाठी खाना भी जानते है और लाठी मारना भी जानते हैं।

पेटलावद विधायक वालसिंह मेड़ा ने कहा, भाजपा की सरकार है लेकिन भाजपा ने कोई विकास नही किया, इस क्षेत्र में जो विकास हुए हैं कांग्रेस पार्टी की ही देन हैं। धमोई तालाब की नहर में भी काम बाकी है नहर का व नल-जल योजना का काम नही किया गया तो प्रदेश के मुख्यमंत्री का घेराव किया जाएगा। और कहा शिवराज मामा झूठ बोलता है, वादे बड़े-बड़े करता है। शिवराज सिर्फ घोषणाए करता है पर काम कुछ नही करता है। अस्पतालो में डॉ. , स्कूलों में मास्टरो का अभाव है इस क्षेत्र में भाजपा सरकार का जरा भी ध्यान नही है। नल -जल योजना के तहत कार्यक्रम में आए ग्रामीणों से मेड़ा ने जन आंदोलन कर धरना प्रदर्शन के लिए हाथ उठाने को कहा। तो सभी ने पुरे जोष के साथ हाथ उठाकर कहा हम बड़े आंदोलन के लिए तैयार है। वही बीच सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। एसडीएम व पीएचई विभाग के अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन का वाचन प्रकाश रांका ने किया। कार्यक्रम का संचालन सलेल खान पठान के किया।

किराना दुकान में चोरी की वारदात, सीसीटीवी फुटेज में कैद पूरी वारदात

रहवासी जागे तो सामान छोड़ भागे चोर, पुलिस गश्त को लेकर खड़े हुए सवाल

माही की गूंज, पेटलावद।

सोमवार-मंगलवार की मध्य रात्रि को नगर के नया बस स्टैंड इलाके में स्थित दीप किराना स्टोर पर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी की पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें चोरों के चेहरे भी साफ दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार चोर छत से दुकान में घुसे और करीब रात साढे 12 बजे दुकान के अंदर रखें गल्ले से नगदी को चुराया। दुकानदार के अनुसार दुकान से लगभग 50 हजार का सामान और नगदी चोरों ने चुराए थे। उसके बाद आसपास के रहवासियों के जाग जाने से चोर सामान छोड़कर भाग निकले तथा चुराई गई नगदी साथ ले गए। रहवासियों ने रात को ही इसकी सूचना दुकान मालिक को दी, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया लेकिन पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही चोर वहां से फरार हो चुके थे।

पुलिस गश्त पर उठे सवाल

नगर के मुख्य मार्ग पर सबसे व्यस्ततम इलाके में स्थित दुकान पर इस तरह चोरों द्वारा आसानी से चोरी की घटना को अंजाम देना। पुलिस गस्त पर सवाल खड़े करती है, क्योंकि मुख्य मार्ग ही सुरक्षित नहीं है तो अंदरूनी इलाकों और दूर बस्तियों के क्या हाल होंगे। बताया जा रहा है कि, इसके पहले भी इसी दुकान में चोरी की घटना घटित हो चुकी थी और यह दूसरी बार घटना घटी। सीसीटीवी फुटेज में चोरों के चेहरे स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी है।

छतो पर होकर ऊपर से अंदर घुसे, लिफ्ट से नीचे गए

किराना दुकान में चोरी करने आये चोरों ने दुकान से सीधे प्रवेश नही किया और दुकान से लगभग चार से पांच मकान की दूरी की छत से होकर दुकान के ऊपर के हिस्से पर पहुचकर दरवाजा खोल कर अंदर प्रवेश किया। दीप किराना पर अंदर लिफ्ट लगी हुई हैं, चोरों ने छत से नीचे आने के लिए लिफ्ट का सहारा लिया। नगर में चर्चा है कि, चोरी में कोई जानकारी रखने वाला शामिल हो सकता है। सीसीटीवी फुटेज में चोरों की तस्वीरे साफ-साफ कैद हो चुकी हैं। सोशल मीडिया पर चोरों की तस्वीरे वायरल हुई है अब देखना है कि, कैमरे में साफ-साफ कैद चोरों तक पुलिस पहुचती है। या हर बार की तरह नाकामयाब रहती हैं।

मिर्ची झोंक कर कपास व्यापारी से लूट

माही की गूंज, थांदला।

ग्राम छोटा जुलवानिया में बुधवार सुबह कपास व्यापारी की दुकान पर ग्राहक बन कपास बेचने आए बदमाशों ने व्यापारियों की आंखों में मिर्ची झोंक कर दो लाख 18 हजार रुपए से अधिक की राशि गल्ले से लुट बदमाश फरार हो गए । व्यापारी राजेश शैतान मल राठौड़ व किशोर राठौड़ ने बताया कि, वह दोनों संयुक्त रूप से कपास का व्यवसाय करते हैं घटना के समय राजेश राठौड़ दुकान पर मौजूद था। जहां फिल्मी स्टाइल में कपास बेचने आए दो बदमाशों ने कपास देने के नाम पर व्यापारियों की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर व पत्थर बरसा कर लूट को अंजाम दिया।

तकनीकी सहयोग से पेयजल समस्या का पंचायत करे समाधान

माही की गूंज,खवासा।

आजादी के अमृत महोत्सव में केंद्र सरकार घर-घर, नल-जल योजना लागू कर रहा है। जिसमें प्रत्येक परिवार के घर तक नल के माध्यम से जल पहुंचाने की योजना है। लेकिन यह योजना कितनी सफल होगी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि, अभी तक गांव में केवल टंकी निर्माण और पाईप डालकर कर्तव्य की इतिश्री कर दी गई, पानी मिलना अभी बाकी है।

कुछ ऐसी ही योजना ग्राम पंचायत खवासा में भी चल रही है। यहां की नल-जल योजना करीब 4 दशक पुरानी है और व्यवस्था को सुधारने के लिए जनता अभी तक 6 सरपंचों को आजमा चुकी है। लेकिन व्यवस्था बजाय सुधारने की जगह बिगड़ते ही जा रही है। वर्तमान में करीब 4 से 6 दिन में एक बार नलों में पानी आता है। जो गर्मियों में करीब 20 से 25 दिन हो जाता है। वर्तमान सरपंच का चुनाव जीती गंगाबाई भी इसी मुद्दे को लेकर जनता के बीच गई थी और जनता ने उन्हें जलसंकट से मुक्ति की आशा के साथ चुनाव में सरपंच की कुर्सी दी है।

पुरानी कहावत है कि, प्यास लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता है। यानी समय रहते व्यवस्था करना आवश्यक है। अभी दिसंबर का महीना चल रहा है। लगभग 3 माह बाद से जल संकट प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन ग्राम पंचायत अभी भी सोई हुई है। जल संकट का सामना करने के लिए उसके पास कोई योजना नहीं है। वही भगवान भरोसे... ये गर्मी भी निकलने की संभावना दिखाई दे रही है।

क्या है योजना

ग्राम खवासा की नल-जल योजना लगभग 4 दशक पुरानी है। पहले एक पुरानी टंकी थी जो उपयोगी कम अनुपयोगी ज्यादा थी से नल-जल योजना प्रारंभ हुई थी। उसके पश्चात ढारियावाले कुँए और नलकूप से सीधे जल वितरण किया जाता रहा कालांतर में आबादी बढ़ने और पेयजल आपूर्ति न होने से बड़े तालाब के पास एक कुआं खोदा गया और गांव की लाइन उससें जोड़ी गई। उसके बाद एक नवीन टंकी का निर्माण किया गया और एक सम्पवेल बनाया गया उससे भी आपूर्ति न होने पर 50 लाख की एक नवीन नल-जल योजना बनाई गई। जो करीब 7 कि.मी दूर ढोलखरा तालाब से पानी लाकर खवासा में नल-जल के माध्यम से पानी वितरण की योजना थी। लेकिन अन्य शासकीय योजना की तरह इस योजना नें भी अपने शैशवकाल में ही दम तोड़ दिया। इतनी बड़ी योजना बगैर किसी तकनीकी विशेषज्ञ के पूरी की गई और नतीजा शून्य ही रहा। यहां तक की ढोलखरा में जो कुआं तालाब के निचले हिस्से में खोदा जाना था वह ऊंचे हिस्से पर खोदा गया जिससे

कुएं में पानी नहीं आया। यही नहीं योजनान्तर्गत पाईप लाईन भी बिना किसी तकनीकी के उबलक ही खोद दी गई जिससे खवासा वासियों को 50 लाख की योजना का लाभ नहीं मिल पाया।

हर सरपंच की हार का कारण जल संकट

पंचायतीराज अधिनियम लागू होने के बाद जितने भी चुनाव हुए, उसमें कोई भी सरपंच दोबारा चुनाव नहीं जीता और उसका एकमात्र कारण जलसंकट ही रहा है। पूर्व सरपंच रमेश बारिया के कार्यकाल में काफी कार्य हुए, मुक्तिधाम पर बाउंड्रीवाल बनवाना उनके कार्यकाल की बहुत बड़ी उपलब्धि आम जनता उनसे खुश भी थे। लेकिन पेयजल के मुद्दे पर उन्होंने जनता से वादा किया था कि, वे निजी नलकूप व निजी टैंकर से खवासा वासियों को जल देंगे और गांव में जल संकट नहीं होने देंगे... वो वादा तो वह पूरा नहीं कर पाए और चुनाव में आम जनता ने उन्हें घर बिठा दिया। वर्तमान चुनाव जीते सरपंच पुत्र शंकर खराड़ी जो कि, महिला सीट होने के कारण अपनी मां के नाम पर चुनाव जीते हैं उनसे आम जनता को काफी उम्मीदें हैं। लेकिन 6 माह के कार्यकाल बीतने के बाद आम जनता खुश नजर नहीं आ रही है। खवासा के पेयजल संकट समाधान का अभी तक वो कोई विज़न नहीं रख पाए है।

आगे क्या करना होगा

निश्चित रूप से खवासा का पेयजल संकट एक विकट समस्या है और इसका हल निकालने के लिए ठोस प्रयास आवश्यक है... मजबूत इच्छाशक्ति की आवश्यकता है... तकनीकी सहयोग की आवश्यकता है... जिसके लिए जनप्रतिनिधियों के साथ तकनीकी विशेषज्ञ आपस में बैठकर एक ठोस योजना बनाएं और उस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए ईमानदारी से प्रयास करें... जनता के हित के लिए निजी हितों का त्याग करें। कहते हैं कि, इच्छाशक्ति अगर मजबूत हो तो इंसान पत्थर से भी पानी निकाल सकता है। खवासा में वर्तमान में लगभग 85 वाल्व के माध्यम से पेयजल वितरण किया जाता है। जिसमें काफी लंबा समय लगता है और गर्मी में तो 20 से 25 दिन में एक बार एक वाल्व का नंबर आता है और गर्मी में 20 से 25 दिन में मात्र आधे घंटे पेयजल मिल पाता है। क्योंकि गर्मी में बड़े तालाब में पानी खत्म हो जाता है और तालाब में पानी खत्म होने से कुएं में पानी की आवक कम हो जाती है। इसके लिए पंचायत को चाहिए कि, सर्वप्रथम वो या तो तालाब का पानी स्टोर करके रखें जिसमें कुएं में आवक कम ना हो या फिर कोई वैकल्पिक व्यवस्था लागू कर जिसके लिए तकनीकी सहयोग भी आवश्यक है इसके लिए पंचायत पीएचई विभाग की मदद ले सकती है। तकनीकी विशेषज्ञ इस पर काम करें कि, जिस प्रकार इन वाल्व की संख्या कम से कम हो सकती है। क्योंकि जितने कम वाल्व होंगे पेयजल वितरण उतना ही आसान होगा और पेयजल की उपलब्धता होने पर एक बार में ही पूरे गांव में जल वितरण किया जा सकता है।

आजादी के इस अमृत महोत्सव में खवासा वासियों को ग्राम पंचायत की नई टीम से उम्मीद है कि, वो इस समस्या के स्थाई हल के लिए न केवल सार्थक प्रयास करेंगे बल्कि दृढ़ इच्छाशक्ति के बल पर उसे अमलीजामा भी पहनाएंगे।

भ्रष्ट जिला प्रशासन इस तरह लील रहा गरीबों को

तीन साल बीत जाने के बाद भी नहीं हुआ कूप की राशि का भुगतान, अधिकारी कह रहे "पैसा नही मिलेगा जो तुझसे बने वो कर लेना"

माही की गूंज, झाबुआ।

जिले में अफसर शाही इतनी हावी होती जा रही है कि भ्रष्टाचार के नित नए आयाम गढ़े जा रहे है। आम आदमी की जैसे कोई सुनवाई ही नहीं है। जिला प्रशासन के आला अधिकारियों को जैसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उनके अधिनस्त किस तरह गरीबों के गले नख दे रहे है। अधिनस्त भ्रष्ट अधिकारी ऐसे कि उच्च अधिकारियों को सावन के अंधे की तरह सबकुछ हरा हरा ही दिखा रहे है। जिले में कागजी घोड़े दौड़ाने का किर्तिमान रचा जा रहा है। जबकि जमीनी हकीकत बिल्कुल इसके उलट नजर आ रही है। जिले में तमाम आला अधिकारी यहां तक कि कलेक्टर मेडम खुदगांव-गांव की खाक छानती फिरती मगर अधिकारियों का रचाया गया आडम्बर उन्हे सावन के अंधे की तरह सबकुछ हरा हरा ही दिखाता। जबकि खामियों को बड़ी आसानी छुपा जाता। इससे जिले में बैठे आला अधिकारियों की कार्य दक्षता पर सवाल खड़े होते नजर आते। उनकी अनुभवहीनता सबको दिखाई भी पड़ती। मीडिया इसे उजागर भी करती लेकिन अधिकारी है कि अपनी कार्यप्रणाली में कोई सुधार करने को मंजूर नही करते। इसका नतीजा यह होता कि अधिनस्त भ्रष्ट अमला गरीबों के गले नख देता और उनका जमकर शोषण करता।

ऐसा ही एक मामला पेटलावद तहसील का सामने आया है। यहां अधिकारियों ने ऐसी कारस्तानी की कि अच्छे- अच्छे बागड़ बिल्ले शर्मा जाए। सरपंच-सचिव ने ग्रामीण को भुगतान का आश्वासन देते हुए कपिलधारा कूप का निर्माण करवा लिया। ग्रामीण ने बाजार व रिश्तेदारों से कर्ज लेकर व उधार में सामग्री क्रय कर कूप का निर्माण भी कर लिया। जनपद स्तर व जिला स्तर के अधिकारियों ने कार्य का निरीक्षण करते हुए खूब तारीफें भी की। जब भी पंचायत में कोई अधिकारी आता उसे इसी कूप निर्माण का निरीक्षण करवाया जाता। क्योंकि पूरे गांव में सबसे अच्छा कूप निर्माण यही था। बाकी जितने कूप ग्राम पंचायत में स्वीकृत हुए थे या तो वे अधूरे या खराब या फिर जमीन से ही नदारद थे। मगर अफसोस कि ग्राम के जिस सबसे अच्छे कूप का निरीक्षण आए दिन अधिकारी करते उस कूप का भुगतान आज दिनांक तक नहीं हो पाया है। जबकि इसकी स्वीकृति 2020-21 में हुई थी। इसी वर्ष यह बनकर तैयार भी हो गया था। मगर राशि के नाम पर हितग्राही को सिर्फ मजदूरी का ही पैसा मिल पाया। बाकी का जो खर्च कूप निर्माण में हुआ वह किसान के माथे पर आज कर्ज बनकर चमक रहा है। हितग्राही कूप निर्माण में लिए गए कर्ज का लगातार तीन वर्षों से ब्याज भर रहा है। अब यह नौबत आ पहुंची है कि उसे यह चिंता सता रही है कि कहीं जमीन से हाथ ना धोने पड़ जाए। शेष भुगतान के लिए जब हितग्राही अधिकारियों के पास पहुंचता तो अधिकारियों के बोल कुछ इस तरह होते कि श्श्तेरे पैसे नहीं आएंगे जो तुझसे बने वो कर लेना।्य

मामला कुछ ऐसा है कि पेटलावद तहसील की ग्राम गोदडिया के एक हितग्राही कोदरसिंह पूजा गामड़ के द्वारा कपिलधारा कूप निर्माण किया गया। कोदर बताता है कि सरपंच और सचिव ने मुझे यह आश्वासन दिया था कि तू कूप निर्माण करवा ले हम इसकी राशि स्वीकृत करवा देंगे। 2020-21 में मेरे नाम से कपिलधारा कूप स्वीकृत हो गया। जिसकी स्वीकृत राशि 2 लाख रुपये थी। सरपंच-सचिव के कहने पर कोदरसिंह ने इसी वर्ष में बाजार व रिश्तेदारों से कर्ज लेकर कूप निर्माण शुरू कर दिया। निर्माण में लगने वाली सामग्री बाजार से उधारी पर उठा ली और निर्माण कुछ ही दिनों में पूर्ण कर दिया। जिसके बाद कोदर के बैंक खाते में कूप निर्माण मे लगी मजदूरी का 82 हजार 710 रुपये का भुगतान जमा हो गया। जिसके बाद कूप निर्माण की बची शेष राशि कोदर को आज दिनांक तक नही मिल पाई है। शेष बची राशि के भुगतान के लिए कोदर पिछले तीन वर्षों से लगातार दर-दर भटक रहा है। कोदर ने अपनी बची शेष राशि लेने को लेकर हर वह प्रयास किए जो उसकी पहुंच में थे, लेकिन उसे अब तक सफलता नही मिल पाई। कोदरसिंह के अनुसार वह शेष राशि के भुगतान के लिए लगातार सरपंच और सचिव के संपर्क में रहा लेकिन कोई नतीजा नही निकला। कई बार जनपद के भी चक्कर लगाए लेकिन वहां से भी कोई समाधान होता दिखाई नही दिया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी पेटलावद व सरपंच-सचिव लगातार यह आश्वासन देते रहे कि आपके बिल आदि हमने जनपद पंचायत में जमा करवा दिए है, जैसे ही बजट आएगा हम आपकी संपूर्ण राशि खाते में डाल देंगे। उसके बाद कोदरसिंह ने परेशान होकर 26 नवम्बर 2022 को मुख्यमंत्री हेल्प 181 पर शिकायत दर्ज करवा दी। मुख्यमंत्री हेल्प लाइन पर शिकायत होते ही जनपद के अधिकारियों का पारा चढ़ गया। अब शिकायत के बाद जब कोदरसिंह जनपद में अपनी शेष राशि के लिए मालूमात हासिल करने पहुंचा तो कोदर के अनुसार वहां के बाउजी गोस्वामी तथा मनरेगा के अधिकारी सिंगारे ने उसे स्पष्ट रूप से कह दिया कि श्श्तेरे पैसे नही आएंगे जो तुझसे बने वो कर लेना। ''तीन साल से अपने कपिलधारा कूप की राशि के लिए भटक रहा कोदर अधिकारियों के इस तरह के रवैये को देखकर डामाडोल हो गया।

कोदरसिंह कहता है कि मेरे साथ जिन लोगों के कूप स्वीकृत हुए थे उन सबकी राशि का भुगतान हो चुका है। जबकि उनमें से कई धरातल पर मौजूद ही नही है। मगर मेरे द्वारा कर्ज लेकर किए गए स्वीकृत कूप निर्माण की राशि का अब तक भुगतान नही हो पाया है। जब अधिकारियों के दौरे के दौरान निरीक्षण की बारी आती थी तो मेरे ही कूप का निरीक्षण करवाया जाता था। मगर अब अधिकारियों व सरपंच सचिव का रवैया मेरे प्रति पूरी तरह से बदल गया है। जनपद के बाबू गोस्वामी और मनरेगा अधिकारी सिंगारे कहता है कि तूने शिकायत की है तो अब तुझे भोपाल से ही पैसा मिलेगा। सरपंच-सचिव के कहने पर मैने कर्जा लेकर 18 फीट आरसीसी से 50 फीट गहरा कूप निर्माण बाजार से कर्ज लेकर बनाया है। अब पिछले तीन वर्षों से ब्याज भर भरकर मेरी जमीन बिकने की नौबत आ चुकी है। अगर कर्जे के कारण मेरी जमीन बिक गई तो मेरे सामने परिवार के भरण पोषण की समस्या खड़ी हो जाएगी। इस संबंध में कोदरसिंह ने मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर से मुलाकात कर अपनी समस्या बताई और कलेक्टर से जल्द बची शेष राशि का भुगतान करवाने का आग्रह किया। हालांकि हितग्राही की इस तरह की परेशानी इस बात का खुला प्रमाण है कि जिले में अफशाही, तानाशाही और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है।

पाटीदार समाज महिला संगठन जिलाध्यक्ष नियुक्त

माही की गूंज, सारंगी।

मध्य प्रदेश पाटीदार समाज संगठन के आदेश अनुसार झाबुआ जिला महिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया गायत्री मंदिर पेटलावद में की गई। जिले के पाटीदार समाज के सभी लोगों की उपस्थिति में निर्वाचन प्रक्रिया पीठासीन अधिकारी शिक्षक लूणचंद पाटीदार झाबुआ एवं हरिराम पाटीदार बनी के सानिध्य में सम्पन्न होकर झाबुआ जिला महिला पाटीदार संगठन अध्यक्ष के लिए प्रीति गेंदालाल पाटीदार के नाम की घोषणा की गई। पाटीदार समाज के सभी महिलाओं-पुरुषों ने प्रीति पाटीदार को बधाइयां दी।

सभा का संचालन डॉक्टर नाथूलाल पाटीदार रायपुरिया ने किया। संगठन में उपाध्यक्ष सोना बेन कैलाश खरड्ड, महामंत्री सुभद्रा बेन रमेश चंद्र रायपुरिया, कोषाध्यक्ष रजनी बेन ओम प्रकाश झाबुआ, सचिव गंगा बेन पुरुषोत्तम रायपुरिया, सहसचिव सविता बेन बाबूलाल रायपुरिया, संगठन सचिव धापू बेन रामलाल रायपुरिया, प्रवक्ता कनक बेन चेतन अमरगढ़, मीडिया प्रभारी लता बेन जीवन पेटलावद, कार्यकारिणी सदस्य अंगुरबाला रजनीश सारंगी, शारदाबेन रविंद्र बनी, दुर्गा बेन दयाराम रायपुरिया, अनीता बलराम पेटलावद, गंगा बेन भागीरथ रायपुरिया, सविता बेन मोहनलाल सारंगी को निर्वाचित किया गया। संगठन के सभी पदाधिकारियों को सारंगी नगर के सभी समाज वर्ग एवं पाटीदार समाज में बधाई एवं शुभकामनाएं दी। पाटीदार समाज जिला संगठन में महिला अध्यक्ष प्रीति बाला गेंदालाल पाटीदार ने कहा, संगठन ने मुझ पर जो विश्वास किया है उस पर मैं खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगी, साथ ही संगठन के सभी सदस्यो का आभार माना।

उप स्वास्थ्य केंद्र में सही से नहीं मिल रही स्वास्थ्य सेवा, सूचना देने के बाद भी ग्राम में नही रहते स्वास्थ्यकर्मी

सुबह 11 से शाम 5 बजे तक खुलता केंद्र, बाकी समय मरीज राम भरोसे

माही की गूंज, अमरगढ़।

पेटलावद से 11 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम अमरगढ़ जहां रेलवे स्टेशन भी है और सैकड़ों लोगों का रोजाना आना-जाना लगा रहता है। ऐसे में किसी का स्वास्थ्य अचानक खराब हो या कोई हादसा हो तो यहां के उपस्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को किसी प्रकार की कोई सुविधा या इलाज नहीं मिल पाती है। रात्रि कालीन कोई इमरजेंसी केस आता है तो उस उपस्वास्थ्य केंद्र पर ताला लगा मिलता है। जिस पर बामनिया या पेटलावद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाने को मजबूर होना पड़ता है और छोटा गांव होने के कारण यहां वाहन की भी कोई सुविधा नहीं मिलती है। ऐसे में मरीज की जान का जोखिम बना रहता है। उपस्वास्थ्य केंद्र अमरगढ़ मात्र एक सीएचओ, एक एएनएम व आशा कार्यकर्ता के भरोसे चल रहा है। यह सीएचओ व एएनएम भी यहां 24 घंटे सेवा उपलब्ध नहीं देकर मात्र 4 से 5 घंटे ही स्वास्थ्य सेवा दे पा रहे है। उपस्वास्थ्य केंद्र सुबह 11 बजे खुलकर शाम 4-5 बजे बन्द कर दिया जाता है। जिसके बाद मरीज राम भरोसे ही रहते है।

बता दे कि, उप स्वास्थ्य केंद्र में सीएचओ दुर्गा खराड़ी पदस्थ है जोकि बामनिया निवास करती है। वही एएनएम रामेश्वरी गेहलोत रतलाम से असमय अपडाउन कर स्वास्थ्य सेवा दे रही है। दोनों ही दोपहर 11 से शाम 4 बजे तक ही उपस्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही है एवं दोनों ही मात्र 4 से 5 घंटे की सेवा देकर अपनी स्कूटी और ट्रेन पकड़कर अपने निवास स्थान पहुंच जाती है। जबकि दोनों ही सीएचओ व एएनएम को उपस्वास्थ्य केंद्र पर ही 24 घंटे सेवा प्रदान करना होता है। दोनों ही नर्स की अनुपस्थिति में शेष समय आशा कार्यकर्ता के भरोसे ही उपस्वास्थ्य केंद्र रहता है। आशा कार्यकर्ता एक छोटी कार्यकर्ता होकर भी 24 घंटे अपनी सेवा प्रदान कर रही है, तो शासकीय सेवा में दोनों सीएचओ व एएनएम 24 घंटे अपनी सेवा क्यों नहीं दे पा रही है की बात ग्रामवासी कह रहे है।

नहीं हो रही डिलीवरी

ग्राम के सरपंच उपस्वास्थ्य केंद्र पर ही महिलाओं की डिलीवरी की सुविधाएं शुरू करने के लिए प्रयासरत है। सरपंच पिन्टूसिंग भुरिया का कहना है कि, ग्राम पंचायत ग्राम के ही उपस्वास्थ्य केंद्र पर डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए तत्पर है। उपस्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ को ग्राम में ही निवास करने के लिए कहा जा रहा है। अगर उनके रवैये में परिवर्तन नही आता है तो शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी। वही उपस्वास्थ्य केंद्र में पूरा स्टाफ महिला का होने के चलते यहां डिलीवरी की सुविधा शुरू करना भी जायज है, वही मामला यही आकर ठहर जाता है कि, पंचायत व ग्रामीण चाहे जितना जोर लगा ले लेकिन दोनों नर्स मात्र 4 से 5 घंटे की सेवा देती है। इस दौरान जो डिलीवरी केस आता है उसे भी मना कर दिया जाता है। ऐसे में उसके परिजनों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहां जननी सुरक्षा गाड़ी की भी सेवा नहीं मिल पा रही है। ऐसे में मरीज को या डिलीवरी वाली महिला को इमरजेंसी में मोटरसाइकिल पर बिठाकर 11 किलोमीटर पेटलावद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाना पड़ता है। ऐसे में प्रसव पीड़ा से उस महिला की जान भी जा सकती है।

इमरजेंसी के दौरान रास्ते में हुई डिलीवरी

उपस्वास्थ्य केंद्र पर डिलीवरी नहीं होने की स्थिति में पेटलावद या बामनिया ले जाते समय कई बार रास्ते में सड़क पर ही डिलीवरी की समस्या उतपन्न हो जाती है। बीते दिनों ग्राम असलिया की प्रसूति महिला की प्रसव पीड़ा अधिक होने के चलते अमरगढ़ के उपस्वास्थ्य केंद्र से थोड़ी ही दूरी पर डिलीवरी रास्ते मे करवाई गई थी। अगर अमरगढ़ में डिलीवरी की सुविधा होती तो प्रसूति महिला की जान जोखिम में डाल रास्ते मे डिलीवरी करवाने की नोबत नही आती।

पल्ला झाड़ रहे जिम्मेदार

उपस्वास्थ्य केंद्र 24 घंटे खुला रहे और प्रसव भी यही हो जिसके लिए कई बार ग्रामीणों एवं सरपंच ने आला अधिकारियों को सूचना कर निवेदन भी किया। लेकिन इस ओर किसी भी जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान नहीं है। ग्रामीणों ने दो बार ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में भी मुद्दा उठाया और अधिकारियों को पंचायत द्वारा भी अवगत करवाया लेकिन अधिकारियों के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। अधिकारी शायद कोई बड़ा हादसा या महिलाओं प्रसव पीड़ा के कारण किसी हादसे का शिकार होने का इंतजार कर रहे हैं। आखिर इस अनदेखी का खेल कब तक चलता रहेगा...?

फरियादी पर धौंस तो आरोपी को संरक्षण जिले में कुछ ऐसी है पुलिसिया कार्यप्रणाली

तीन महीने हुए एफआईआर को, आरोपी खुलेआम घूम रहा, रोज देता है जान से मारने की धमकी, पुलिस कहती गिरफ्तारी हो गई, कोर्ट में पैश करेंगे तब आना

माही की गूंज, झाबुआ।

मध्यप्रदेश के पश्चिमी छोर के आदिवासी बाहुल जिले की कानून व्यवस्था का इन दिनों भगवान ही मालिक है। जिले में पुलिस का रवैया ऐसा कि, फरियादी की कोई सुनवाई नहीं होती और आरोपी व अपराधी को खुला संरक्षण मिलते देखा जा सकता है यह कोई नई बात नहीं है। ऐसे कई मामले है जो जिले में कानून व्यवस्था को धत्ता बता रहे है। माही की गूंज ने अपने पिछले अंक में ही इस तरह के एक मामले को उजागर किया था। जिसमें पुलिस खुद फरियादी को धमकाती और आरोपी को संरक्षण देती दिखाई पड़ रही थी। इस बात का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आम जनता का क्या होगा...? ऐसा नहीं है कि, पुलिस विभाग में काबिलियत नही है, मगर निकम्मापन और कामचोर पद्धति से पुलिस महकमा पूरी तरह से खोखला हो चुका है। पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के नित नए आयाम गढ़े जा रहे है। इसका भी प्रमाण देने की हमें आवश्यकता नहीं है। रिश्वतखोरी और माफियाओं के टूकड़े तोडने के कहानी किस्से आए दिन अखबारों के पन्नों पर नजर आते है। बावजूद इसके भी अगर महकमें का आला अधिकारी यह दम्भ भिड़े कि, जिले में पुलिस व्यवस्था चॉक चौबंद है तो यही कहा जाएगा कि, ''आंख का अंधा नाम का नयनसुख'' मतलब कुछ लोग नाम के अनुरूप अपना कार्य नहीं करते और ऐसे ही लोगों के लिए यह कहावत कही गई है।

माही की गूंज ने अपने पिछले अंक में भी पुलिस महकमें की कुछ इस तरह की कारस्तानी को उजागर किया था। जिसमें ''शिक्षक ने की अपनी पत्नि के नाम से उगरानी, दोगुना का लालच देकर की ठगी, पीड़ित भटक रहा दर-दर'' शीर्षक से समाचार प्रकाशित कर पुलिस की कथनी और करनी को उजागर किया था। मामले में राणापुर पुलिस द्वारा ठगी का शिकार हुए फरियादी की एफआईआर दर्ज न करते हुए, यह कहते हुए आवेदन ले लिया गया था की आरोपी शासकीय सेवा में है इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। फरियादी के मुख्यमंत्री हेल्प लाइन पर शिकायत के बाद पुलिस ने उसे थाने पर बुलाया और डरा-धमका कर मुख्यमंत्री हेल्प लाइन की शिकायत वापस करवाई गई थी। इस मामले में सीधे तौर पर पुलिस ने आरोपी को खुला संरक्षण दिया।

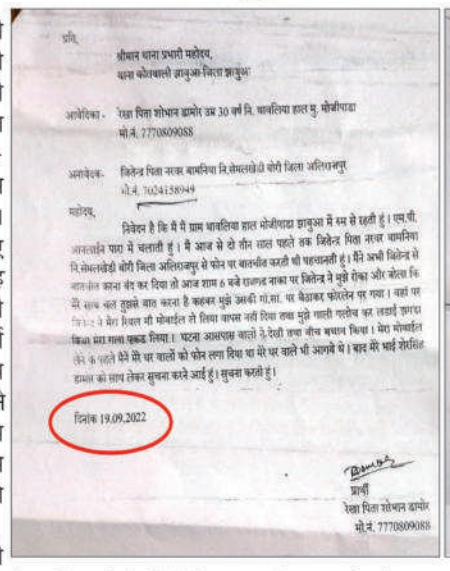

प्रति,
श्रीमान थाना प्रभारी महोदय,
थाना कोतवाली झाबुआ जिला झाबुआ

आवेदिका - रेखा पिता शोभान डामोर उम्र 30 वर्ष नि. थावलिया हाल मु. मोजीपाड़ा
मो.नं. 7770809088

अनावेदक - जितेन्द्र पिता नरवर बामनिया नि.सेमलखेड़ी बोरी जिला अलिराजपुर
मो.नं. 7024158049

महोदय,

निवेदन है कि मैं मैं ग्राम थावलिया हाल मोजीपाड़ा झाबुआ में रूम से रहती हूं। एम.पी. ऑनलाईन पारा में चलाती हूं। मैं आज से दो तीन साल पहले तक जितेन्द्र पिता नरवर बामनिया नि.सेमलखेड़ी बोरी जिला अलिराजपुर से फोन पर बातचीत करती थी पहचानती हूं। [illegible]

दिनांक 19.09.2022

प्रार्थी
रेखा पिता शोभान डामोर
मो.नं. 7770809088

N.C.R.B
I.I.F.-I

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दं.प्र.सं. के तहत)

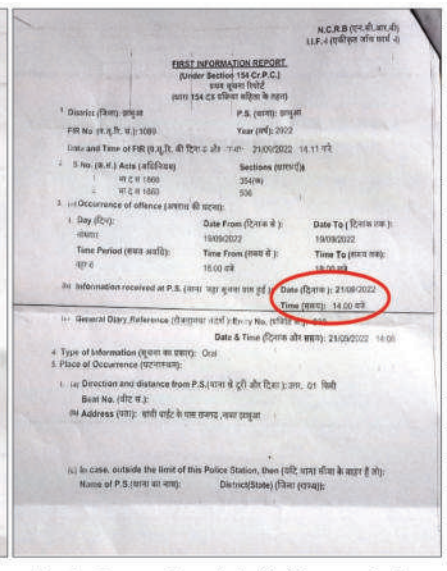

1. District (जिला): झाबुआ P.S. (थाना): झाबुआ Year (वर्ष): 2022
FIR No: 1089
Date and Time of FIR: 21/09/2022 14:11
2. S.No. Acts (अधिनियम) Sections (धारायें)
भा.द.वि 1860 354(क)
भा.द.वि 1860 506
3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
1. Day (दिन): सोमवार Date From: 19/09/2022 Date To: 19/09/2022
Time Period: पहर 6 Time From: 18:00 बजे Time To: 18:00 बजे
(b) Information received at P.S. Date (दिनांक): 21/09/2022 Time (समय): 14:00 बजे
(c) General Diary Reference Date & Time: 21/09/2022 14:06
4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Oral
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
1. (a) Direction and distance from P.S.: 01 किमी
Beat No. (बीट न.):
(b) Address (पता):
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then: Name of P.S. District/State

ऐसा ही एक और मामला पुलिस की कारस्तानी का ही झाबुआ कोतवाली पर सामने आया है। मामले में रेखा पिता शोभान डामोर उम्र 30 निवासी थावलिया हाल मुकाम मौजीपाड़ा झाबुआ ने एक आवेदन 19 सितम्बर को पुलिस कोतवाली झाबुआ में दिया था। युवती ने अपने दिए आवेदन में शिकायत की थी कि, मैं रेखा पिता शोभान डामोर निवासी थावलिया हाल में मोजीपाड़ा झाबुआ में रूम किराये से लेकर रहती हूं। एमपी ऑनलाइन की दुकान पारा में चलाती हूं। मैं करीब दो-तीन साल पहले तक जितेन्द्र पिता नरवर बामनिया निवासी सेमलखेड़ी बोली जिला आलीराजपुर से फोन पर बातचीत करती थी। मैं उसे पहचानती हूं। अभी जितेन्द्र से मेरी कोई बातचीत नहीं है। 19 सितम्बर को शाम 6 बजे जितेन्द्र ने मुझे राजगढ़ नाके पर रोका और बोला कि, मेरे साथ चल तुझसे बात करनी है। उसके बाद वह मुझे मोटर सायकल से फोरलेन पर ले गया और मेरा मोबाईल छीनकर मुझसे गाली-गलोच कर झगड़ा करने लगा। उसने मेरा गला भी दबाने की कोशिश की। आसपास वालों ने बीच-बचाव किया। जितेन्द्र ने जब मेरा मोबाईल लिया उसके पहले ही मैने मेरे घर वालों को फोन पर सूचना दे दी थी। इसलिए घर वाले भी वहां पर आ गए। जिसके बाद में अपने भाई शेरसिंह को लेकर थाने पर सूचना देने पहुंची। पुलिस ने रेखा से उस समय आवेदन ले लिया। लेकिन तत्काल एफआईआर दर्ज नहीं की। करीब आवेदन के दो दिन बाद पुलिस ने रेखा की एफआईआर दर्ज की।

पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार पुलिस ने यह माना कि, घटना 19 सितम्बर को घटी। लेकिन उसी एफआईआर में पुलिस यह भी दर्शा रही है कि, सूचना 21 सितम्बर को प्राप्त हुई। जबकि रेखा का थाने पर दिया गया आवेदन यह बताता है कि, रेखा के द्वारा तुरंत घटना के बाद 19 सितम्बर को ही पुलिस को सूचना दे दी गई थी। सूचना दिनांक के दो दिन बाद पुलिस का एफआईआर लिखना कई सवालों को खड़ा कर रहा है। हालांकि दो दिन बाद ही सही लेकिन पुलिस ने मामले में धारा 354 (क) और 506 में प्रकरण दर्ज कर लिया। इधर रेखा डामोर का यह कहना है कि, पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली लेकिन आरोपी जितेन्द्र को अब तक गिरफ्तार नही किया गया है। आरोपी आज भी आए दिन मुझसे विवाद करता और जान से मारने की धमकी देता रहता है। मुझे उससे अब भी जान का खतरा बना हुआ है। पारा में मेरी दुकान पर आकर आए दिन आरोपी जितेन्द्र के रिश्तेदार व जितेन्द्र फोन पर मुझे मारने व विवाद करने की धमकी देते रहते है। आरोपी जितेन्द्र पहले से ही शादीशुदा है और उसके बच्चे भी है। मैं जब भी शिकायत लेकर पुलिस के पास जाती हूं मुझे बातों में उलझा कर रवाना कर दिया जाता है। पुलिस थाने पर मुझे यह कहा जाता है कि, आरोपी जितेन्द्र की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। हम तुम्हे फोन कर देंगे तो आ जाना। थाने पर शिकायत करने के बाद अब तक तीन माह से ज्यादा का समय गुजर चुका है। एफआईआर हो जाने के बावजूद आरोपी जितेन्द्र पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नही की जा रही है। इन तीन महीनों के दौरान रेखा ने पुलिस अधीक्षक से भी गुहार लगाई। पुलिस अधीक्षक ने फिर से थाना प्रभारी झाबुआ को मामले को संज्ञान में लेने के निर्देश दिए। मगर पुलिस अधीक्षक के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए थाना कोतवाली से अब तक कोई कार्रवाई नही हुई। आरोपी अब भी खुले आम घूम रहा है। आरोपी जितेन्द्र पेशे से ड्रायवर है और अभी वर्तमान में वह बोरी से इंदौर चलने वाली बस का चालक है। पुलिस की इस तरह की कार्यप्रणाली ने रेखा के मन में कई सवाल खड़े कर दिए है। आरोपी और पुलिस के बीच कहीं कोई गोटी तो नहीं बैठ गई या आरोपी की तरफ से पुलिस को कोई आश्वासन तो नहीं मिला है। जिसकी बदौलत पुलिस आरोपी को खुला संरक्षण दे रही है। तीन माह बाद भी जितेन्द्र पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिसिया कार्यप्रणाली से त्रस्त होकर रेखा मंगलवार को कलेक्टोरेट में जनसुनवाई में पहुंची थी। अपना आवेदन लेकर वह रजिस्ट्रेशन पर्ची लेने पहुंची तो उसे यहां से यह कहकर रवाना कर दिया गया कि, आपका आवेदन यहां नहीं लिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन पर्ची नहीं मिलने के कारण रेखा कलेक्टर तक पहुंच ही नही पाई। बावजूद इसके वह कलेक्टोरेट में जनसुनवाई खत्म होने का इंतजार करती रही कि, जनसुनवाई के बाद कलेक्टर मेडम से सीधी मुलाकात हो जाए और वे उसकी इस समस्या को संज्ञान में लेकर उसका निराकरण करवाए। लेकिन हाय री किस्मत... घंटों इंतजार के बाद भी रेखा की कलेक्टर से मुलाकात नही हो पाई और उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ा।

संपादकीय

चीन में कोरोना ने एक बार फिर दी दस्तक

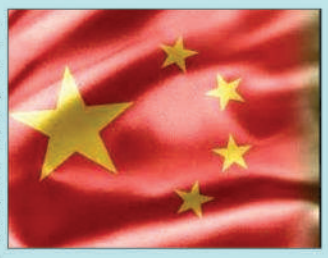

हाल के दिनों में कोरोना संक्रमण के खिलाफ चीन सरकार की सख्त ज़ीरो टॉलरेंस नीति व लॉकडाउन से उकताए लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया था। यहां तक कि शी जिनपिंग को भी निशाने पर ले लिया गया था। उसके बाद जन आंदोलनों के दबाव में सरकार झुकी और सख्त प्रतिबंधों में ढील दी। लेकिन ज़ीरो कोविड नीति में ढील देने के बाद चीन में कोरोना संक्रमण में अप्रत्याशित तेजी आई है। यहां तक कि अब हालात बेकाबू हो गए हैं। चीन के अस्पताल कोरोना संक्रमितों से भरे हैं और बड़ी संख्या में लोगों के मरने की खबरें आ रही हैं। कुल मिलाकर स्थिति भयावह है। आशंका जताई जा रही है कि, चीन में कोरोना की तीन लहरें आएंगी जिसमें लाखों लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल, इस भयावह संकट से चीन का हेल्थ सिस्टम ही चरमरा गया है। अस्पतालों में बड़ी संख्या में शवों के पड़े होने की बात पश्चिमी मीडिया में कही जा रही है। हालांकि, चीन में सूचना माध्यमों पर सख्त पहरा होने के कारण ठीक-ठीक आंकड़े सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञ संकट को बड़ा बता रहे हैं। दरअसल, सर्दियों के कारण स्थिति के भयावह होने की आशंका जताई जा रही हैं। स्कूल-कॉलेज बंद करने के आदेश दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि, ज़ीरो कोविड नीति में ढील देने के कारण स्थितियां खराब हुई हैं। ऐसा नहीं है कि, केवल चीन में ही हालात खराब हुए हैं जापान व दक्षिण कोरिया में भी लाखों की संख्या में संक्रमितों के सामने आने की बात कही जा रही है। दरअसल, चीन समेत कई देशों में टीकाकरण के लक्ष्य पूरे नहीं हुए हैं। चीन में अस्सी साल से अधिक के आधे लोगों को ही तीन डोज मिल पायी हैं। संकट यह भी है कि चीन की वैक्सीन की रोग प्रतिरोधक क्षमता अन्य देशों की वैक्सीन के मुकाबले कम बताई जा रही है।

ऐसा नहीं है कि, भारत पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो गया है। हाल के दिनों में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के कोरोना संक्रमित होने की बात सामने आई। बीच-बीच में कुछ खास लोगों के संक्रमित होने की चर्चा तो मीडिया में होती है, लेकिन आम आदमी की क्या स्थिति है कहना कठिन है। एक तो संक्रमण के आंकड़ों की पूरी तरह निगरानी होती नजर नहीं आ रही है। दूसरे, सरकारें भी अपनी सुविधा से आंकड़ों को उजागर करती हैं। लेकिन हाल के दिनों में ठंड की शुरुआत में बड़ी संख्या में लोगों के बुखार-खांसी से पीड़ित होने के मामले प्रकाश में आते रहे हैं। यह घातक तो नहीं नजर आया लेकिन इसका प्रभाव सामान्य वायरल से अधिक देखा गया। कई राज्यों में ऐसे मामले प्रकाश में आए। अभी इस बारे में अध्ययन की जरूरत है कि, हमारे परिवेश में व्याप्त कोविड वायरस का प्रभाव किस हद तक निष्प्रभावी है। हाल के दिनों में टीकाकरण के साइड इफेक्ट को लेकर भी आम लोगों में कई तरह के विमर्श सामने आते रहे हैं। हालांकि, इस बारे में कोई वैज्ञानिक अध्ययन तो सामने नहीं आए, लेकिन मामले कोर्ट-कचहरियों तक गूंजते रहे हैं। बहरहाल, इतना तो कहा जा सकता है कि यह निष्कर्ष देना जल्दबाजी होगी कि देश से कोरोना वायरस हमेशा के लिए चला गया है। ऐसे में हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि, कोरोना संकट के दौरान बचाव के जिन उपायों पर हमने भय से अमल किया था, वे आदतें हमारे जीवन का हिस्सा बन जानी चाहिए। खासकर सफाई, मास्क व सुरक्षित दूरी का परहेज भी हमें किसी आशंका से दूर कर सकता है। हमें दुनिया के कई देशों में तेजी से पांव पसार रहे कोरोना संक्रमण को एक चेतावनी के रूप में लेना चाहिए। साथ ही हर नागरिक को अपने स्तर पर जिम्मेदार व्यवहार के जरिए इस चुनौती के प्रति सतर्क रहना चाहिए। निस्संदेह, हमारी सजगता व सतर्कता में ही हमारा बचाव निहित है। यदि हम संयमित व सतर्क व्यवहार का पालन करते हैं तो हम किसी भी आसन्न संकट को टाल सकते हैं।

अभिव्यक्ति की आज़ादी का सम्मान करें सरकारें

विश्वनाथ सचदेव

लगभग दो वर्ष पहले एक किताब छपी थी अंग्रेजी में 'फ्रैक्चर्ड फ्रीडम'। चर्चा भी हुई थी इसकी और बिकी भी काफी यह पुस्तक। वर्ष भर पहले कोबाड गांधी की इस पुस्तक का मराठी अनुवाद प्रकाशित हुआ था 'फ्रैक्चर्ड फ्रीडम' तुरंगात आठवणी व चिंतन। अनुवाद अनघा लेले ने किया था और मराठी पाठकों ने भी इसे हाथो-हाथ लिया। कुछ ही दिन पहले महाराष्ट्र सरकार ने इस अनुवाद को पुरस्कृत कर पुस्तक को फिर से चर्चा में ला दिया था। लेखक कोबाड गांधी और अनुवादक अनघा लेले, दोनों को खूब बधाइयां मिलीं। फिर अचानक महाराष्ट्र सरकार जैसे किसी नींद से जागी और पुस्तक को दिया गया पुरस्कार रद्द करने की घोषणा कर दी। कारण यह बताया गया कि, इस पुस्तक में लेखक ने नक्सलियों का महिमामंडन किया है और सरकार इसका समर्थन नहीं कर सकती। अवार्ड रद्द किए जाने की घोषणा के साथ-साथ उस समिति को भी भंग कर दिया गया, जिसने पुस्तक को पुरस्कृत करने की सिफारिश की थी। सरकार का कहना है कि समिति का दायित्व बनता था कि वह सरकार की जानकारी में यह बात लाती कि इस पुस्तक में नक्सलियों का जयगान है!

मराठी के साहित्यिक जगत में सरकार की इस समूची कार्रवाई की तीव्र आलोचना हो रही है। अनेक नामचीन रचनाकारों ने भी मराठी भाषा साहित्य से संबंधित पुरस्कार लेने से इन्कार कर दिया है। प्रज्ञा पवार, शरद बाविस्कर, आनंद करंदीकर, सुहास पलसीकर जैसे साहित्यकारों ने सरकारी समिति से भी इस्तीफा दे दिया है। सरकारी कार्रवाई का विरोध करने वालों को सरकार का यह कदम सरकार का तानाशाही रवैया जैसा लग रहा है। कइयों को इमरजेंसी की याद आ रही है जिसमें साहित्यकारों को अपनी बात कहने के अधिकार से वंचित किया गया था।

निःसंदेह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देश के हर नागरिक का संविधान प्रदत्त अधिकार है और जनतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाली कोई सरकार ऐसा नहीं कर सकती। महाराष्ट्र सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त करने और इस्तीफ़ों की यह प्रक्रिया अभी जारी है। सवाल यह भी है कि क्या संबंधित पुस्तक में सचमुच नक्सलवाद का महिमामंडन करके हिंसात्मक कार्रवाई का समर्थन किया गया है। यह सही है कि पुस्तक के लेखक कोबाड गांधी कभी माओवाद से प्रभावित रहे थे। नक्सली हिंसा को बढ़ावा देने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था और 10 वर्ष तक उन्हें जेल में रखा गया था। फिर वे न्यायालय से आरोपमुक्त हुए। जेल से रिहा होने के बाद ही उन्होंने यह पुस्तक लिखी थी और उनका कहना है कि पुस्तक नक्सलवाद की प्रशंसा नहीं, आलोचना करती है। यह भी अपने आप में एक विडंबना ही है कि माओवाद को बढ़ावा देने के जिस आरोप में पुस्तक को दिया गया पुरस्कार वापस लेने की घोषणा की गई है, उसी पुस्तक को लिखने के कारण माओवादियों ने लेखक को अपने संगठन से अलग कर दिया था। उन्हें लगा कि पुस्तक माओवादी आंदोलन को बदनाम करने वाली है!

यहीं यह भी रेखांकित किया जाना जरूरी है कि दलितों, पिछड़ों के संघर्ष के प्रति अपनी सहानुभूति को कोबाड गांधी ने कभी छुपाया नहीं। वे और उनकी पत्नी स्वर्गीय अनुराधा दोनों पिछड़ों के अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार सक्रिय रहे हैं पर दोनों का यह भी कहना रहा है कि उन्होंने हिंसात्मक कार्रवाई का समर्थन कभी नहीं किया। ज्ञातव्य है कि सन्? 60-70 के दशक में बिहार के नक्सलबाड़ी स्थान से दलितों-आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक आंदोलन प्रारंभ हुआ था। आगे चलकर भले ही इस आंदोलन में ऐसे लोगों का प्रवेश हो गया जो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हिंसात्मक कार्रवाई को भी जायज मानते थे, पर आंदोलन से मूल रूप से सहानुभूति रखने वाले बहुत से लोग अहिंसात्मक संघर्ष के ही पक्षधर रहे। कोबाड गांधी का कहना है कि उनकी गणना ऐसे ही लोगों में होनी चाहिए।

कोबाड गांधी का यह भी कहना है कि, उनकी यह संस्मरणात्मक आत्मकथा उनके 10 वर्ष के जेल के अनुभवों पर आधारित है। साथ ही वे यह भी कहते हैं कि उनका उद्देश्य सामाजिक असमानता को समाप्त करना है। वे यह कहते हैं कि इस असमानता को समाप्त करने के लिए संघर्ष के लक्ष्यों को बदलना पड़ेगा और समानता के संघर्ष की बजाय सबकी खुशी का संघर्ष करना होगा। यह संघर्ष सबकी प्रसन्नता, स्वतंत्रता और अच्छे मूल्यों के लिए होना चाहिए।

बहरहाल, देश का जनमानस आज यह तो चाहता है कि पिछड़ों को विकास का समान और पर्याप्त अवसर मिले पर नक्सली हिंसा को यह देश स्वीकार नहीं कर सकता। कोबाड गांधी भी यही कह रहे हैं। उनका मानना है कि अपनी किताब में उन्होंने जेल के अपने अनुभवों की कथा लिखी है, जिन लोगों से वह जेल में मिले उनकी बात समझाने की कोशिश की है। इस कोशिश को देश विरोधी नहीं समझा जाना चाहिए।

पर यहां मुद्दा साहित्य और अभिव्यक्ति के प्रति सरकार के दृष्टिकोण और रवैये का भी है। पहली बात तो यह कि अनघा लेले को अनुवाद के लिए पुरस्कृत किया गया है। अनुवाद अपने आप में एक कला और सृजन है। यहां सवाल पुस्तक के कथ्य का उतना नहीं है, जितना अनुवाद की क्वालिटी का है। इस दृष्टि से देखें तो पुरस्कार रद्द किया जाना कतई तार्किक नहीं लगता। फिर इस बात को भी समझा जाना जरूरी है कि साहित्य और संस्कृति के संदर्भ में महाराष्ट्र की एक शानदार परंपरा रही है। साहित्य और साहित्यकार को यहां विशेष सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। राजनेताओं का समाज में अपना स्थान है, पर राजनीति करने वाले सिर्फ इसलिए निर्णायक की भूमिका में नहीं आ जाते कि वे राजनेता हैं। महाराष्ट्र में साहित्य सम्मेलनों में राजनेता मंच पर नहीं, श्रोताओं के बीच बैठते हैं, बैठाये जाते हैं। सिर्फ सत्ता में होने के कारण उन्हें यह अधिकार नहीं मिल जाता कि वे साहित्य और साहित्यकार के बारे में फरमान जारी कर सकें।

दूसरे, साहित्यिक विधाओं के लिए सरकार द्वारा पुरस्कार दिए जाने का मतलब सरकार द्वारा किसी को उपकृत किया जाना नहीं है। यह पुरस्कार विशेषज्ञ समितियों के माध्यम से दिए जाते हैं। फ्रैक्चर्ड फ्रीडम के मराठी अनुवाद को एक विशेषज्ञ समिति ने पुरस्कार के योग्य पाया था। पुरस्कार की घोषणा अवश्य सरकार द्वारा की गई थी पर मात्र इससे पुरस्कार सरकार विशेष का अथवा सरकार में बैठे राजनीतिक दल का पुरस्कार नहीं हो जाता। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हर नागरिक का यह दायित्व बनता है कि वह सरकार को उनके कर्तव्य के प्रति आगाह करता रहे। महाराष्ट्र सरकार को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए।

जनतांत्रिक मूल्यों का तकाज़ा है कि, अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य के अधिकार की रक्षा हो और रचनाकार को आदर सहित पुरस्कृत किया जाए।

राहुल गांधी की अंग्रेजी-भक्ति?

डॉ. वेद प्रताप वैदिक

राजस्थान में राहुल गांधी ने अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई की जमकर वकालत कर दी। राहुल ने कहा कि भाजपा अंग्रेजी की पढ़ाई का इसलिए विरोध करती है कि वह देश के गरीबों किसानों मजदूरों और ग्रामीणों के बच्चों का भला नहीं चाहती है। भाजपा के नेता अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में क्यों पढ़ाते हैं? राहुल ने जो आरोप भाजपा के नेताओं पर लगाया वह ज्यादातर सही ही है लेकिन राहुल जरा खुद बताए कि वह खुद और उसकी बहन क्या हिंदी माध्यम की पाठशाला में पढ़े हैं? देश के सारे नेता या भद्रलोक के लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में इसीलिए भेजते हैं कि भारत दिमागी तौर पर अभी भी गुलाम है। उसकी सभी ऊँची नौकरियां अंग्रेजी माध्यम से मिलती हैं। उसके कानून अंग्रेजी में बनते हैं। उसकी सरकारें और अदालतें अंग्रेजी में चलती हैं। भाजपा ने अपनी नई शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा को स्वभाषा के माध्यम से चलाने का आग्रह किया है जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन भाजपा और कांग्रेस दोनों की कई प्रांतीय सरकारें अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को प्रोत्साहित कर रही हैं। किसी विदेशी भाषा को पढ़ना एक बात है और उसको अपनी पढ़ाई का माध्यम बनाना बिल्कुल दूसरी बात है। मैंने पहली कक्षा से अपनी अंतरराष्ट्रीय पीएच.डी. तक की परीक्षाएं हिंदी माध्यम से दी है। स्वभाषा के माध्यम से पढ़ने का अर्थ यह नहीं है कि आप विदेशी भाषाओं का बहिष्कार कर दें। मैंने हिंदी के अलावा संस्कृत जर्मन रूसी और फारसी भाषाएं भी सीखीं। अंग्रेजी तो हम पर थोप ही दी जाती है। राहुल का यह तर्क सही है कि गरीब और ग्रामीण वर्ग के बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में नहीं पढ़ते इसलिए वे पिछड़ जाते हैं। वे भी अंग्रेजी पढ़ें और अमेरिका जाकर अमेरिकियों को भी मात करें। राहुल की यह बात मुझे बहुत पसंद आई लेकिन मैं पूछता हूं कि हमारे कितनी विद्यार्थी अमेरिका या विदेश जाते हैं? कुछ हजार छात्रों की वजह से करोड़ों छात्रों का दम क्यों घोटा जाए? जिन्हें विदेश जाना हो वे साल-दो साल में उस देश की भाषा जरूर सीख लें लेकिन किसी विदेशी भाषा को 16 साल तक अपनी पढ़ाई का माध्यम बनाए रखना और उसे करोड़ों बच्चों पर थोप देना कौनसी अक्लमंदी है? हिरण पर घांस क्यों लादी जाए? यदि हमारे नेता लोग चाहते हैं कि गरीबों ग्रामीणों पिछड़ों किसानों और मजदूरों के बच्चों को भी जीवन में समान अवसर मिलें तो देश में सभी बच्चों के लिए स्वभाषा-माध्यम की पढ़ाई अनिवार्य होनी चाहिए। अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई पर कठोर प्रतिबंध होना चाहिए। विदेशी संपर्कों के लिए हमें सिर्फ अंग्रेजी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। विदेश-व्यापार विदेश नीति और उच्च-शोध के लिए अंग्रेजी के साथ-साथ फ्रांसीसी जर्मन चीनी रूसी अरबी हिस्पानी जापानी आदि कई विदेशी भाषाओं की पढ़ाई भी भारत में सुलभ होनी चाहिए। दुनिया के किसी भी संपन्न और शक्तिशाली राष्ट्र में छात्र-छात्राओं की पढ़ाई का माध्यम विदेशी भाषा नहीं है।

काहिली से दम तोड़ती दिल्ली की जीवनरेखा

दिल्ली सरकार यमुना को 2025 तक साफ करके नहाने लायक बनाने का लगातार दावा करती रही है। समय-समय पर कई कवायद करने का दावा भी करती रही है, लेकिन हकीकत इसके बिलकुल उलट है। असलियत यह है कि बीते पांच साल में यमुना नदी पहले से और ज्यादा प्रदूषित हो गयी है। वह जानलेवा बीमारियों का सबब बन चुका है। इसकी पुष्टि तो पर्यावरण विभाग तक कर चुका है। यदि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मानें तो हालत इतनी खराब है कि यमुना के पानी में फीकल कोलिफार्म की मौजूदगी अधिकतम स्वीकृत मानक से 6.8 से भी अधिक है। विडम्बना यह है कि इनकी तादाद दिनोदिन तेजी से बढ़ रही है जो खतरनाक संकेत है। यदि इलाके वार इसका जायजा लें तो यमुना के पानी में फीकल कोलिफार्म की मौजूदगी वजीराबाद में अधिकतम स्वीकृत संख्या से 6.8 गुणा ज्यादा है, आईटीओ पुल के पास यह बढ़कर 80 गुणा से ज्यादा हो गया है और ओखला बैराज तक आते-आते यह 132 गुणा हो गया है जो असगरपुर पहुंचने पर 272 गुणा का आंकड़ा पार कर गया है। सबसे ज्यादा चिंता का सबब यह है कि यमुना के पानी में आक्सीजन की मात्रा शून्य पायी गयी है।

गौरतलब है कि, वजीराबाद से लेकर ओखला के बीच घरेलू अपशिष्ट जल और रसायन युक्त औद्योगिक अपशिष्ट को ले जाने वाले 22 बड़े नाले सीधे-सीधे यमुना में गिरते हैं। यमुना की कुल लम्बाई का मात्र 22 किलोमीटर का इलाका दिल्ली में पड़ता है। हकीकत यह है कि यही 22 किलोमीटर का इलाका यमुना को सबसे ज्यादा प्रदूषित करता है। पूरी यमुना में जो गंदगी है, उसमें 80 फीसदी तो दिल्ली की ही गंदगी है। यमुनोत्री से प्रयागराज तक बहने वाली यमुना का मात्र दो फीसदी हिस्सा ही दिल्ली में बहता है। लेकिन उसी में वह 80 फीसदी प्रदूषित हो जाती है। मात्र 20 किलोमीटर के दायरे में हर दो किलोमीटर पर दो नाले यमुना को प्रदूषित कर रहे हैं। नाले गिरते ही यमुना का पानी नाले के पानी समान काला हो जाता है, उसमें झाग बनना शुरू हो जाता है। नतीजतन उसमें अमोनिया का स्तर बढ़ने लगता है और वह दुर्गंधमय हो जाता है। योजना अनुसार हर नाले पर एसटीपी लगायी जानी थी, वह काम भी आज तक नहीं हो सका है।

गौरतलब है कि, दिल्ली में दो सरकारें हैं। केन्द्र में भाजपा की सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आप की सरकार है। लेकिन यमुना साफ कर पाने में दोनों दलों की सरकारें नाकाम रही हैं। जबकि यमुना सफाई अभियान को शुरू हुए दो दशक से भी अधिक का समय बीत चुका है। यमुना को टेम्स बनाने का सपना तो सपना ही बनकर रह गया है। उस दशा में जबकि केन्द्र सरकार यमुना की सफाई के लिए 1500 करोड़ और दिल्ली की सरकार एक बार 2074 करोड़ और दूसरी बार 200 करोड़ से ज्यादा राशि खर्च कर चुकी है, लेकिन यह समझ से परे है कि इस राशि का हुआ क्या? वर्ष 2015 के अपने घोषणापत्र में आप पार्टी ने कहा था कि यमुना दिल्ली का लम्बे समय से हिस्सा रही है लेकिन अब दिल्ली की जीवनरेखा यमुना मर रही है। वह तब बचेगी जब हम दिल्ली के 100 फीसदी सीवेज का ट्रीटमेंट सुनिश्चित करेंगे और औद्योगिक गंदगी को यमुना में बहाये जाने से सख्ती से रोका जायेगा। यही नहीं, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत यमुना की सफाई के लिए केन्द्र ने 4000 करोड़ से अधिक राशि के 13 प्रोजेक्ट स्वीकृत किये, लेकिन खेद है कि अभी तक केवल दो ही पूरे हो सके हैं।

सवाल यह है कि जब दिल्ली में यमुना की स्थिति इतनी बदहाल है, उस दशा में दिल्ली से आगे मथुरा-आगरा और उसके आगे यमुना की स्थिति क्या होगी, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। आगरा में तो 17वीं शताब्दी में बनी विश्व प्रसिद्ध इमारत ताजमहल से होकर यमुना बहती है। उस हालत में ताजमहल के आसपास गोल्डी काइरोनोमस नामक एक विशेष किस्म के कीड़े पाये जाते हैं। यह कीड़े ताजमहल पर अपनी गंदगी से हरे धब्बे डाल रहे हैं जिससे इस इमारत का संगमरमर बदरंग हो रहा है। इसका अहम मूल कारण वहां यमुना में पानी की कमी और यमुना में सीवर का सीधे-सीधे गिरना है। साथ ही यमुना के पानी में आक्सीजन की मात्रा का स्तर अत्यधिक कम होने के कारण हजारों मछलियां और जल जीवों की हो रही मौतें हैं।

असलियत में यमुना सफाई की दिशा में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, अदालतें और पर्यावरण विभाग आदि सख्त नियम बनाते हैं, सुधार हेतु आदेश देते हैं लेकिन भ्रष्टाचार और प्रशासनिक तंत्र के नाकारेपन की इसमें सबसे बड़ी भूमिका है। उसमें भी राजनीतिक नेतृत्व की प्रबल इच्छाशक्ति का अभाव इसका सबसे बड़ा कारण है। कहने को तो कहा जाता है कि नदियां जीवन का आधार हैं, इनके किनारे संस्कृतियां पनपी हैं और यह पुण्यसलिला हैं, पुण्यदायिनी, जीवनदायिनी हैं, इनको मां के रूप में पूजा जाता है, जन्म से लेकर अन्त समय तक के धार्मिक कर्मकाण्ड इन्हीं के किनारे होते हैं आदि-आदि। यदि ऐसा वास्तव में मानव की सोच होती तो यमुना तो कब की टेम्स बन चुकी होती। देश की सभी नदियां कब की शुद्ध, निर्मल, अविरल और सदानीरा बन चुकी होतीं।

लेखक :- ज्ञानेन्द्र रावत

नफरत और अफवाहबाजी की गिरफ्त में सोशल मीडिया

तनवीर जाफरी

वर्तमान युग में कंप्यूटर-इंटरनेट के सबसे बड़े चमत्कार के रूप में सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफ़ार्म्स को देखा जा रहा है। इसके माध्यम से जहां दूरस्थ इलाक़ों की जो ख़बरें व सूचनायें कई कई दिनों बाद ज़िला व प्रदेश मुख्यालयों में पहुंचा करती थीं वे अब बिना समय गंवा ये तत्काल या लाईव पहुँच जाती हैं। कोरोना काल के समय से शुरू हुआ वर्क फ़्रॉम होम और स्टडी फ़्रॉम होम का चलन भी इसी कंप्यूटर-इंटरनेट तकनीक और इससे संबंधित विभिन्न ऐप की देन है। दुनिया के लाखों लोग जो अपने परिवार से दस-बीस-पचास-साठ वर्ष पूर्व किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितिवश बिछड़ गये थे वे फ़ेसबुक जैसे सोशल मीडिया के अन्य चमत्कारिक प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से अपने परिवार से मिल चुके हैं। शिक्षा, व्यवसाय, विद्युत, स्वास्थ्य, प्रशासनिक काम-काज बैंक, सेना, रेल, विमानन, अंतरिक्ष आदि दुनिया का शायद कोई भी क्षेत्र इस समय कंप्यूटर -इंटरनेट और सोशल मीडिया से अछूता नहीं है। परन्तु कभी कभी इसी कंप्यूटर -इंटरनेट पर आश्रित सोशल मीडिया के फ़ेसबुक, ट्वीटर व व्हाट्सऐप जैसे अनेक माध्यमों के होने वाले दुरूपयोग को देखकर तो ऐसा प्रतीत होता है गोया हमारे वैज्ञानिकों ने बन्दर के हाथ में अस्तूरा थमा दिया है।

इस समय जहाँ सोशल मीडिया सैक्स ठगी और दूसरे कई साइबर अपराधों की ज़द में आ चुका है और तमाम लोग अपनी नक़ली आईडी बना कर आम लोगों को विभिन्न तरीक़ों से अपने जाल में फंसाने की कोशिश में लगे हुये हैं। वहीं इस माध्यम का इस्तेमाल बड़े ही सुनियोजित तरीक़े से नफ़रत और अफ़वाह फैलाने के लिये भी किया जा रहा है। और इन नफ़रत और अफ़वाह बाज़ी का सिर्फ़ एक मक़सद होता हैसमाज को धर्म समुदाय के आधार पर विभाजित करना उन में परस्पर एक दूसरे के प्रति नफ़रत पूर्ण उत्तेजना फैलाना और इस प्रदूषित वातावरण को दंगेफ़साद तथा सामुदायिक हिंसा तक पहुँचाना। कुछ पेशेवर क़िस्म के ख़ाली बैठे लोग जिनका किसी सेवा या रोज़गार से कोई वास्ता नहीं ऐसे लोग ख़ास तौर पर फ़ेसबुक, व्हाट्सऐप और ट्वीटर जैसे विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म्स का दुरूपयोग करते रहते हैं और सोशल मीडिया पर मिलने वाले कचरा ज्ञान को बिना सोचे समझे और उन समाचारों व विषयों की पुष्टि किये बिना कॉपी पेस्ट या फ़ॉरवर्ड करने लग जाते हैं।

इसी क्रम में न जाने कितनी हिंसक वीडिओ जो किसी दूसरे देशों की पुरानी वीडिओज़ होती हैं उन्हें अपने देश की ताज़ी वीडिओज़ बताकर देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जाती है। इस नफ़रत और अफ़वाहबाज़ी को प्रसारित करने के लिये अनेक लोग व इसी मिशन से जुड़े अनेक संगठन कंप्यूटर -इंटरनेट के इस दुरूपयोग को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नाम देते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग समाज में ऐसे भी हैं जो दूसरों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सिर्फ़ इसलिये उंगली उठाते हैं क्योंकि व्यक्त किये गये विचार उनके अपने विचारों व सोच के अनुरूप नहीं होते। इसलिये दूसरों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की क़द्र करने के बजाये स्वयं अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताकर उसका विरोध शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि गत दिनों कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह के उद्घाटन के अवसर पर आम तौर पर विवादित विषयों पर ख़ामोश रहने वाले सुपर स्टार अमिताभ बच्चन ने नागरिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर अपने विचार व्यक्त करते हुये कहा कि ''अब भी नागरिकों की स्वतंत्रता पर सवाल उठाए जाते हैं।''

अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीनी सैनिकों के बीच गत 9 दिसंबर को हाथापाई होने का समाचार आया था। प्राप्त ख़बरों के अनुसार इस दौरान भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब देते हुये चीनी सैनिकों को उनकी सीमा की ओर खदेड़ दिया था। बताया जाता है कि चीन के लगभग 300 सैनिक तवांग के यांगत्से में भारतीय पोस्ट को वहां से हटाने के मक़सद से पहुंचे थे। परन्तु भारतीय व चीनी सेना के बीच चली धक्का मुक्की का एक पुराना वीडिओ जोकि पूर्व में होने वाली भारतीय चीनी सेना की झड़प का वीडिओ था उसे इस तवांग की ताज़ी ख़बर के साथ जोड़कर ख़ूब वायरल किया गया। बांग्लादेश के कई साम्प्रदायिक हिंसा व तोड़ फोड़ के वीडिओज़ को बंगाल का बताकर वायरल किया गया। इसी तरह तालिबानों या पाकिस्तान के हिंसा के कई वीडिओज़ कश्मीर की हिंसा के वीडीओ बताकर वायरल किये गये। इसतरह की सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों घटनायें हो चुकी हैं।

यहां सोचने और चिंतन करने का मुख्य विषय यह है कि आख़िर जानबूझ कर और एक सुनियोजित नेटवर्क का हिस्सा बनकर नफ़रत और अफ़वाहबाज़ी फैलाने वाले तत्व हमारे देश और समाज को कितना नुक़सान पहुंचा रहे हैं ? जो भारतवर्ष अनेकता में एकता के लिये दुनिया में अपनी मुख्य पहचान रखता था उसी देश की एकता को छिन्न भिन्न करने के लियेउसी समाज में नफ़रत का ज़हर घोलने के लिये झूठ और अफ़वाहबाज़ी का कितना बड़ा सहारा लिया जा रहा है ? मेरे विचार से ऐसे लोग या ऐसे लोग द्वारा संचालित नेटवर्क किसी एक व्यक्ति के हत्यारे से भी बड़े दोषी और अपराधी हैं। क्योंकि यह अपने इस नापाक मिशन के माध्यम से पूरे सामाजिक परिवेश को ही अपराधपूर्णहिंसक और ज़हरीला बनाने पर आमादा हैं। और इससे भी बड़े अफ़सोस का विषय यह है कि प्रायः इसतरह का घिनौना काम सत्ता की देख रेख में और उसकी सरपरस्ती में किया जा रहा है। देश में ऐसे कई कई वीडियो व आडियो सामने आ चुके हैं जिनमें पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारों की आवाज़ या इसतरह के कोई अन्य विवादित नारों की आवाज़ पेस्ट कर दी गयी। उसके बाद इसी झूठी सामग्री के आधार पर बाक़ायदा पूरा बवाल काटा जाता है। गोदी मीडिया इन अफ़वाहबाज़ों के साथ खड़ा हो जाता है। स्वयं को राष्ट्रवादी और दूसरों को देशद्रोही प्रमाणित करने की पूरी कोशिश की जाती है। झूठ को सच और सच को झूठ साबित करने की कोशिशें की जाती हैं।

ऐसे में यह सवाल उठना लाज़िमी है कि जिस सोशल मीडिया से सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों को सकारात्मक ढंग से पेश करने की उम्मीद थी जैसा कि हमारे वैज्ञानिकों द्वारा सोचा भी गया थाक्या अब वही सोशल मीडया नफ़रत और अफ़वाहबाज़ी की गिरफ़्त में आ चुका है?

संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने खून से मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

माही की गूंज, मंदसौर। साहिल अगवान

प्रदेश में इन दिनों संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जिसके चलते वे प्रदेशभर में हड़ताल पर हैं। इसी कड़ी में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने मंदसौर में अपने खून से मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। जिसमें मांग की गई कि, 5 जून 2018 की घोषणा के अनुसार संविदा नीति को लागू किया जाए। रेगुलर कर्मचारियों के समकक्ष उन्हें वेतन देने के साथ ही उन्हें परमानेंट भी किया जाए। इसके अतिरिक्त अब तक निकाले जा चुके संविदा कर्मचारियों को वापस काम पर भी लाया जाए। ज्ञात हो कि, प्रदेशभर में इन दिनों 32 हजार संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर हैं।

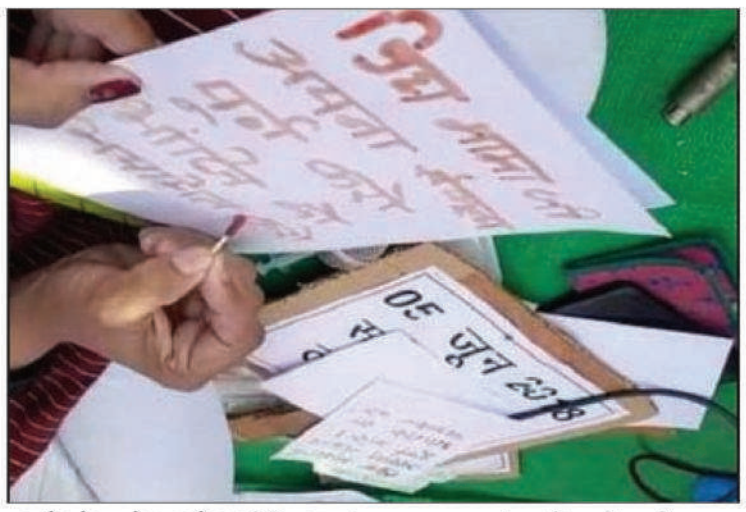

खून से लिखा मांग पत्र

प्रदर्शनकारी संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी को परेशानी हो, लेकिन हम मजबूरन हड़ताल प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने सीएम को खून से पत्र लिखकर मांग रखी है कि हमारी मांगों को मानते हुए हमें स्थाई किया जाए। इसके अलावा समान कार्य का समान वेतन प्रदान किया जाए, जबकि हमारे निलंबित कर्मचारी साथियों को भी वापस लिया जाए। उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाती हैं, तब तक हम हड़ताल और प्रदर्शन जारी रखेंगे।

जब तक मांग नहीं मानी जाती हड़ताल जारी रहेगी

करीब 32 हजार संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल के संबंध में जो जानकारी बताई गई। उसके अनुसार 5 जून 2018 की नीति के अनुरुप सरकार संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समकक्ष वेतन और नियमतीकरण किया जाए। अन्यथा जब तक मांग नहीं मानी जाती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी।

बता दे कि, इस समय प्रदेशभर में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। ये हड़ताल संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ मध्यप्रदेश के बैनर तले की जा रही है। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के नियमितीकरण और निष्कासित किए गए कर्मचारियों की बहाली को लेकर ये हड़ताल है। ऐसे में प्रदेश भर में 32 हज़ार संविदा कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का कहना है कि जो कर्मचारी 10, 15 वर्ष से काम कर रहे हैं, उन्हें नियमित किया जाना चाहिए। वहीं 8, 10 वर्ष से काम कर चुके बड़ी संख्या में कर्मचारी जिन्हें निष्कासित कर दिया गया है, उनकी बहाली की जानी चाहिए। ऐसे में उनकी ये मांगे जब तक नहीं मानी जातीं, तब तक हड़ताल जारी रहेगी।

टोल नाके से निकलते ही अचानक धूं-धूं कर जल उठी कार

ड्राइवर ने बचाई खुद की जान

माही की गूंज, रतलाम।

महू-नीमच हाईवे पर ढोढर के पास एक कार अचानक धूं-धूं करके जलने लगी। मामला रतलाम-बदनावर रोड पर चिकलिया टोल नाके के सामने मंगलवार को सामने आया। बदनावर की तरफ से आ रहे एक कार सवार की कार टोल नाके से निकलने के कुछ दी ही देर बाद उसमें से धुआं निकलने लगा। कार चालक को जैसे ही इसकी जानकारी लगी तो वह कार को साइड में खड़ी करके सुरक्षित उतर गया।

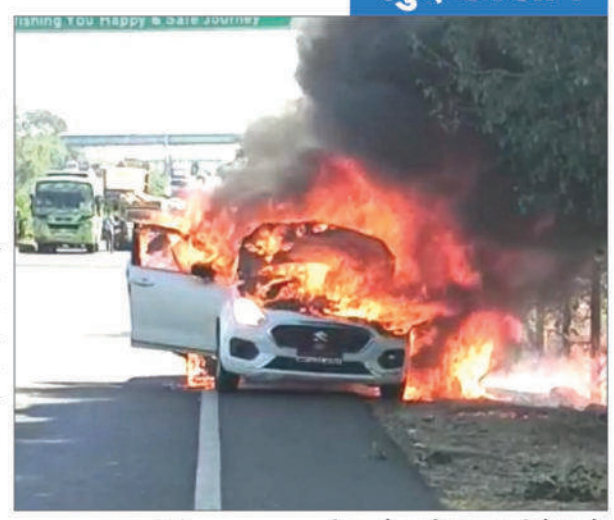

पलक झपकते खाक हो गई पूरी कार

कार चालक बदनावर की वीरमणि कॉलोनी निवासी धनंजयसिंह ने बताया कि, वे कार लेकर टोल नाके से महज कुछ ही फीट की दूरी पर आए और अचानक धुआं निकलने लगा तो उन्होंने साइड में कार खड़ी कर दी। उतरकर आए और देखा तब तक आग की लपटें निकलने लगी और कुछ ही मिनटों में पूरी कार धूं-धूं करके जलने लगी। देखते ही देखते पूरी कार जलकर खाक हो गई। कार चालक समय से गाड़ी से बहार आ गया जिससे ड्राइवर को कोई नुकसान नहीं हुआ।

रतलाम आ रहे थे किसी काम से

धनंजय ने बताया कि, वे खेती करते हैं और किसी काम से अपनी कार से रतलाम के लिए दोपहर में निकले थे। बदनावर से निकलने के बाद उनकी कार में कुछ भी गड़बड़ी नहीं थी लेकिन जैसे ही टोल नाके पर टोल की पर्ची कटाने के बाद आगे बढ़े तो अचानक ही कार के बोनट से धुआं निकलता दिखाई दिया। उन्हें शंका हुई तो उन्होंने कार को सडक़ की साइड में खड़ा करके देखना चाहा। इसी दौरान कार में शार्ट सर्किट से आग लगी और आग की लपटें निकलने लगी। फायर बिग्रेड को सूचना दी गई। फायर लारी पहुंचती और आग बुझाती तब तक कार जल चुकी थी।

सरकारी स्कूल की दो नाबालिग बच्चियों का अपहरण, प्रकरण दर्ज, खोजबीन जारी

माही की गूंज, रतलाम।

शहर के समीप मांगरोल गांव के शासकीय स्कूल की कक्षा नौंवी में पढने वाली दो नाबालिग बच्चियों का अपहरण हो गया। सालाखेडी पुलिस ने आपराधिक प्रकरण दर्ज बच्चियों की खोजबीन प्रारंभ कर दी है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, मांगरोल के शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल की कक्षा नौवी में पढने वाली एक 14 वर्षीय और दूसरी 16 वर्षीय बालिका प्रतिदिन की तरह सुबह स्कूल गई थी। स्कूल की आधी छुट्टी साढे दस बजे होती है। साढे दस बजे तक दोनो बालिकाएं स्कूल में मौजूद थी, लेकिन स्कूल की छुट्टी होने के बाद दोनो ही बालिकाएं घर नहीं पंहुची। दोपहर तक जब बच्चियां घर नहीं पंहुची, तो उनके अभिभावकों ने पुलिस से सम्पर्क किया। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपहरण का आपराधिक प्रकरण दर्ज कर बालिकाओं की खोजबीन प्रारंभ कर दी। पुलिस सूत्रों के अनुसार, बच्चियों के अपहरण के मामले में फिलहाल किसी संदेही का नाम सामने नहीं आया है।

पत्नी के हत्यारे पति को मिली अजीवन कारावास की सजा

माही की गूंज, मंदसौर।

पत्नी की हत्या के मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने अलग रह रही पत्नी को बुलाकर गला दबाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद उसने शव को गड्ढे में डालकर उस पर पत्ते डाल दिए थे। सजा जिला एवं स ा न्यायाधीश अजीतसिंह ने दी।

जि ला अभियोजन अधिकारी निर्मला सिंह चौधरी ने बताया, विकास अठवाल ने मल्हारगढ़ थाने में बहन सपना की गुमशुदगी दर्ज कराई। उसने जानकारी दी की उसकी बहन की शादी 2019 में नीमच निवासी राहुल घारू से हुई थी। पुलिस ने जांच के दौरान राहुल से पूछताछ की। इसमें उसने बताया पत्नी से दो माह से कोई बातचीत नही हुई। इस पर पुलिस ने मृतिका और उसके पति के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकाली। इसके बाद पुलिस ने एक बार फिर राहुल से पूछताछ की। उसने बताया 20 नवंबर 2020 को पत्नी सपना ने फोन लगाकर कहा कि, वह मंदसौर पीजी कॉलेज आई हुई हैं। राहुल दोस्त की बाइक लेकर पीजी कॉलेज पहुंचा। पत्नी सपना को मिलने व बातचीत करने का बोलकर बाइक पर बैठाकर होमगार्ड लाईन के पीछे जंगल में ले गया। वहां पत्नी ने कहा, आप मेरे माता-पिता व भाई से बात करो। जिस पर मैंने कहा कि, आपके परिवार ने मेरे व मेरे मा-बाप के खिलाफ दहेज प्रताडना का केस कायम करवा दिया है अब मैं उनसे क्या बात करू। जिसके बाद नीमच में साथ रहने की बात को लेकर दोनों में झगडा हो गया। इस पर उसने पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसके शव को एक गड्ढे मे डालकर ऊपर पत्तों से छिपा दिया। बयान के आधार पर पुलिस ने पहुंचकर तलाश की। यहां पेड के पत्तों से ढंकी लाश मिली। इसकी पहचान भाई विकास व नटवर ने की। साक्ष्य व तर्कों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी राहुल पिता जनमेश घारू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन का संचालन उप संचालक अभियोजन एसके जैन ने किया।

बच्चियां अपने सिंगल फोटो सोशल प्लेटफॉर्म शेयर करने से बचें, गलत साइड्स पर इस्तेमाल करते हैं सायबर अपराधी- चंद्रवंशी

माही की गूंज, शाजापुर।

पोलायकला में शासकीय हायर सेकेंडरी उच्चतर विद्यालय अरनिया खुर्द एवं ग्राम पाड़लिया के स्कूल में अभा ग्राहक पंचायत के क्षेत्रीय सह संगठन मंत्री घनश्याम चंद्रवंशी ने बताया कि, समाज को सायबर क्राइम मुक्त बनाना है, क्राइम करने वाले बड़ी योजनाबद्ध तरीके से नए-नए माध्यम से अपडेट होकर प्राइम करते हैं। अपराधी समय के अनुसार अपडेट होकर हम सबके निजी डेटा की खरीदी करके उस के माध्यम से अपराध करते हैं। हमें भी अपडेट होना पड़ेगा और जागरूक रहना पड़ेगा। ताकि हमारे आस पास कोई भी ऐसी घटना न हो पाए। उन्होंने बच्चों को विशेष तौर पर कहा कि, इंस्टाग्राम पर अपनी सिंगल फोटो न डालें। इंस्टाग्राम पर या अन्य प्लेटफार्म पर किसी अनजान व्यक्ति से दोस्ती नहीं करना चाहिए। सोशल प्लेटफॉर्म लव जिहाद के बड़े अड्डे बन चुके हैं। इनका उपयोग करते समय सतर्क रहने की आवश्यकता है।

पोलाय के उत्कृष्ट विद्यालय में पुलिस चौकी के प्रभारी अंकित मुकाती भी उपस्थित रहे उन्होंने बच्चों को बताया कि, किन-किन ऐप को डाउनलोड करना चाहिए। कई ऐप ऐसे हैं जिनसे हमारे मोबाइल की क्लोनिंग हो जाती है। और मोबाइल क्रिमिनल संचालित करने लगता है। कार्यक्रम के दौरान मोर्चा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के आईटी सेल प्रभारी कालापीपल विधानसभा विष्णु चरण परमार, शाला के प्राचार्य सुनील कुमार वर्मा, शिवचरण मालवीय, भगवान सिंह परमार, श्रीराम पटेल आदि उपस्थित रहे।

जिला दण्डाधिकारी ने जारी किए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश

माही की गूंज, शाजापुर।

वर्तमान में पतंगबाजी करने के लिए आम जनता द्वारा चाइना डोर का उपयोग किए जाने की सूचना प्राप्त होने और आने वाले मकर संक्रांति पर्व पर पतंगबाजी करने की परम्परा को दृष्टिगत रखते हुए जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर दिनेश जैन द्वारा भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत चाइना डोर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। उल्लेखनीय हैं कि, चाइना डोर नायलोन से बनी होकर सामान्य डोर से पक्की होने के कारण इससे घातक घटनाये समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाश में आई है। आने वाले दिनो में मकर सक्रांति का पर्व मनाया जायेगा तथा बड़ी संख्या मे आम जनता पतंग बाजी करेंगी तथा पतंगबाजी के दौरान चाइना डोर का उपयोग किया जाना जन सामान्य एवं किसी भी व्यक्ति और परिंदो के स्वास्थ्य एवं जीवन के लिए घातक होकर खतरा उत्पन्न हो रहा है। इसे देखते हुए जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर जैन ने लोक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं लोगो के जीवन को जोखिम से बचाने के लिये पतंगबाजी के दौरान चाइना डोर के उपयोग पर प्रतिबंधित लगाया है।

जारी किए गए आदेश के तहत जिले में कोई भी व्यक्ति पतंगबाजी के दौरान चाइना डोर का उपयोग एवं संग्रहण नहीं करेगा। पतंग की दुकानों पर चाइना डोर न तो विक्रय के लिए रखी जाएगी और न ही उसका संग्रह एवं विक्रय के लिए प्रदर्शित की जाएगी। चूंकि चाइना डोर का विक्रय करने तथा उपयोग करने वाले व्यक्ति निश्चित नहीं होने के कारण दण्ड प्रक्रिया संहिता 144 (2) के तहत लोक हित में आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। आदेश तत्काल प्रभावशील 31 जनवरी 2023 तक प्रभावशील रहेगा। इस अवधि में आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में माना जाएगा।

सीएम के आगमन से पूर्व कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण

माही की गूंज, शाजापुर।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के शाजापुर जिले के संभावित भ्रमण कार्यक्रम को देखते हुए आयोजन के लिए चयनित स्थल बापू की कुटिया पर की जा रही तैयारियों का निरीक्षण कलेक्टर दिनेश जैन एवं पुलिस अधीक्षक जगदीश डावर ने किया। इस अवसर पर अशोक नायक, विजय सिंह बेस, नगरपालिका अध्यक्ष प्रेम जैन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे।

कलेक्टर जैन ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि, सौंपे गए दायित्वों का भली-भांति निर्वहन करें और समारोह के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो, इस पर ध्यान दें। अधिकारियों को जिस सेक्टर के लिए तैनात किया गया है, वहां की संपूर्ण व्यवस्था की जिम्मेदारी उन्ही की होगी। इस मौके पर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक ने तैयार किये जा रहे हेलीपेड, सभा स्थल, पार्किंग स्थल आदि का भी निरीक्षण किया।

स्कूल वालों ने निकाला तो वापस भर्ती कराने के लिए कलेक्टर ने डिप्टी कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी के साथ स्कूल पहुंचाया

माही की गूंज, रतलाम।

जिला कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में मंगलवार को आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई में शहर के उंकाला रोड निवासी बालक कासिम जो कि 9 वीं कक्षा का छात्र है। उसको स्कूल वालों ने निकाल दिया तो जनसुनवाई में बालक अपने माता-पिता के साथ आया।

कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने संवेदनशीलता के साथ उसकी परेशानी सुनी तथा डिप्टी कलेक्टर त्रिलोचन गौड एवं जिला शिक्षा अधिकारी केसी शर्मा को निर्देश दिए कि वह बालक के साथ रतलाम माणक चौक स्कूल जाएं बालक को वापस भर्ती करवाएं। कलेक्टर के निर्देश पर डिप्टी कलेक्टर त्रिलोचन गौड़ स्कूल पहुंचे जिला शिक्षा अधिकारी अपनी गाड़ी में बालक को बैठाकर माणक चौक स्कूल ले गए और भर्ती करवाया। जिला कलेक्टर सूर्यवंशी के इस कार्य की नगर में चर्चा और सराहना दोनों हो रही है।

फोटो 1 क्र 223

एडॉप्ट एन आँगनवाड़ी कार्यक्रम के तहत सामग्री भेंट

माही की गूंज, शाजापुर।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाए जा रहे ÷एडॉप्ट एन आँगनवाड़ी÷ कार्यक्रम के अंतर्गत कलेक्टर दिनेश जैन के निर्देशानुसार एवं प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी सुश्री नीलम चौहान के मार्गदर्शन में जिले में आँगनवाड़ी की आधारभूत आवश्यकताए जनसहयोग से जुटाई जाकर बच्चों को आँगनवाड़ी में बेहतर सेवाए प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। ताकि बच्चे आँगनवाड़ी की सेवाओं का अधिक से अधिक लाभ लेकर स्वस्थ व पोषित हो सके।

इसी तारतम्य में परियोजना पोलायकलां सेक्टर अकोदिया वार्ड-8 की कार्यकर्ता श्रीमती शांति मीणा द्वारा जन सहयोग के अनुरोध पर अपाक्स के संभागीय अध्यक्ष डॉ. सुशील गहलोत ने 5 हजार 300 रूपए की एक अलमारी एवं एक हजार 450 रूपए के छत पंखा का सहयोग दिया गया।

युवकों से ज्यादा युवतियां आई मंच पर, संस्कृत में परिचय देकर किया गौरवान्वित

माही की गूंज, शाजापुर।

अग्रवाल समाज के दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय युवक-युवती परिचय सम्मेलन में हजारों समाजजन जुटे-सेवाभावी समाजजनों का सम्मान किया गया। श्री अग्रवाल बायोडाटा बैंक उज्जैन द्वारा आयोजित अग्रवाल समाज के पंचम निःशुल्क अग्रवाल युवक-युवती अंतरराष्ट्रीय परिचय सम्मेलन में दूसरे दिन हजारों समाजजन शामिल हुए। युवकों से ज्यादा युवतियों ने मंच पर आकर परिचय दिया। वहीं एक युवक ने संस्कृत में परिचय देकर गौरव का अनुभव कराया।

संस्था अध्यक्ष शैलेन्द्र मित्तल एवं कार्यक्रम संयोजक रवि बंसल ने बताया कि, श्री अग्रवाल बायोडाटा बैंक उज्जैन द्वारा इंदौर रोड़ स्थित मित्तल एंड रिसोर्ट नानाखेड़ा में आयोजित विशाल निःशुल्क परिचय सम्मेलन में रविवार को 100 से अधिक प्रत्याशियों ने मंच से परिचय दिया। स्क्रीन के माध्यम से भी परिचय कराए गए। साथ ही दहेज प्रथा का विरोध करते हुए मंच से संदेश दिया कि, न दहेज लेंगे न देंगे।

सचिव जितेन्द्र अग्रवाल एवं कोषाध्यक्ष पुरूषोत्तम मोदी ने बताया कि, सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव, देवास महापौर गीता अग्रवाल, राजेन्द्र अग्रवाल इंदौर, श्याम बंसल, रवि अग्रवाल ब्यावरा के रूप में मौजूद रहे। समाज में अग्रणी कार्य करने वाले समाजसेवी प्रेमसुख अग्रवाल, नरेन्द्र मंगल, संस्था के वरिष्ठ संस्थापक सदस्य कमलेश मित्तल, ओमप्रकाश गर्ग, पुरषोत्तम मोदी को श्रीफल, प्रमाण पत्र, शाल भेंटकर सम्मानित किया। प्रचार प्रसार प्रभारी अजीत मंगलम ने बताया कि युवक युवतियों की प्रविष्टियों की आकर्षक परिचय पुस्तिका का प्रकाशन भी परिचय सम्मेलन में किया गया। सम्मेलन में मध्यप्रदेश के अलावा बैंगलोर, मुंबई, हरियाणा, पंजाब सहित देश विदेश से प्रत्याशी शामिल हुए। शुभारंभ अवसर पर तृप्ति मित्तल, श्रध्दा गर्ग, सोनिया मित्तल, प्रियंका अग्रवाल, पूनम गर्ग, तृप्ति बजाज, दीपिका अग्रवाल ने नृत्य प्रस्तुति दी। ललिता मित्तल, सरोज अग्रवाल, सलोल अग्रवाल ने स्वागत किया। संचालन दीपक मित्तल ने किया। दूसरे दिन भी युवक युवतियों के अभिभावकों को भी लक्की ड्रा द्वारा पुरस्कृत किया गया।

इस दौरान विजय मित्तल, दीपक मित्तल, विजय गर्ग, कमलेश मित्तल, ओपी गर्ग, राधेश्याम अग्रवाल, रमेश शाह, पवन मित्तल, सुरेन्द्र सिंहल, सुरेन्द्र मित्तल, अनिल गर्ग, प्रो. डीके सिंहल सहित हजारों समाजजन मौजूद रहे।

सरकारी जमीन और भू-माफियाओं का खेल, गोया चरणोई की भूमि पर काट दिए प्लाट

माही की गूंज, पेटलावद।

बामनिया में सरकारी भूमि की हेरा-फेरी कोई नई बात नही है। यहां करोडों की भूमि भू-माफियाओ ने राजस्व रेकॉर्ड में हेरा-फेरी कर ठिकाने लगा दी। वही राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने ही पुराने अधिकारीयो को बचाने के लिए खुद भी फर्जीवाड़े में वसुली खुद कर इस हेरा-फेरी में शामिल हो गए। विगत दिनों बामनिया ग्राम के सर्वे नम्बर 104,105 ओर 106 को लेकर मामला सामने आया था। यहां जयस संगठन बिरसा मुंडा की मूर्ति स्थापित करना चाहता था और उसके लिए शासकीय सर्वे नम्बर 105 की भूमि की मांग की थी। लेकिन भू-माफिया के द्वारा इस मामले में सेटिंग बिठाकर मामला 105 से सर्वे नम्बर 104 पर लाया गया और बिना पुराने रिकॉर्ड को देखे नए रिकॉर्ड के आधार पर नपती कर मामले को दबाया गया। दूसरी ओर ग्राम पंचायत द्वारा सर्वे नम्बर 105 के सीमांकन के लिए तहसील कार्यालय में आवेदन दिया गया। जिसे बिना कार्रवाई के फाइलों में दबा दिया गया। उक्त भूमि पर निर्माण कार्य शुरू होने के बाद एक बार फिर सरकारी भूमि की हेरा-फेरी का बड़ा मामला उजागर होने की संभावना हैं ।

सरकारी खेलः गोया चरणोई की भूमि पर काट दिए प्लाट

पेटलावद तहसील की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत बामनिया तत्कालीन समय से ही झाबुआ विरासत के समय से रेलवे स्टेशन होने के कारण औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता था तत्कालीन समय अंग्रेजों के शासन काल में वर्ष 1931-32 मैं सेटलमेंट बंदोबस्त होने के बाद से मध्यप्रदेश भू-राजस्व अधिनियम 1959 लागू होने के बाद ग्राम बामनीया

यहा बनाई गई दुकान

शिकायत के बाद तेज़ी से जारी है निर्माण कार्य

विवादित भूमि जो शिकायतकर्ता अनुसार सरकारी भूमि है

मे तत्कालीन वर्ष 1973 -74 में एक ही बार पेटलावद तहसील की ग्राम बामनिया का सेटलमेंट बंदोबस्त किया गया। जिसके बाद से आज तक किसी भी प्रकार से राजस्व भूमि आबादी, नजूल भूमि का सेटलमेंट नहीं हुआ है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में लगातार 1973-74 के बाद से आज दिनांक तक भू-माफिया और अधिकारियों की मिलीभगत से संबंधित गोचर भूमि, चारागाह भूमि एवं अन्य राज्य शासन की भूमि के नंबरों को बदल कर राजस्व की बेशकीमती भूमियों को प्लाट काटकर बेचा जा रहा है।

22 हेक्टेयर जमीन 4 सरकारी कार्यालय को छोड़कर माफियाओं के कब्जे में

ग्राम बामनीया की राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 1958-59-60- से लेकर लगातार वर्ष 1972-73-1974-गोचर भूमि सर्वे नंबर 86/1/1/1/1/की स्थिति देखे तो तत्कालीन समय मे 22 -हेक्टेयर के बड़े रकबे में वर्ष 1962- 63 से लेकर लगातार सेटलमेंट के पहले 1972-73 में गोया चरणोंई की भूमि पर खसरा खाता पाचशाला संशोधित प्रविष्टि 13 और 14 नंबर पर अतिक्रमण के रूप में निवासी बामनिया गोबरिया पिता धुला नारू का 0.40- की सरकारी भुमि पर अतिक्रमण रहा था जिसके बाद में वर्ष 1966 से -वर्ष 1969- तक अलाउद्दीन रोशन खा गणपत दौला गवली जिसके नाम पर और भी कई शासकीय चारागाह की जमीन दूसरे सर्वे नंबर पर दर्ज है और उसको भी बैच दिया गया है के, द्वारा सर्वे नंबर 86/1/1/1/1/ पर अतिक्रमण कर कब्जा किया गया था जिनके द्वारा राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से वर्ष 1990 के बाद में राजस्व रिकॉर्ड अनुसार रास्ता गोचर भूमि को बैच दिया गया।

सरकारी पड़त भूमि पर काट दिये प्लाट चल रहा निर्माण

मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1960 लागू होने के बाद में तत्कालीन वर्ष 1974 को ग्राम बामनिया का एक ही बार बंदोबस्त(सेटलमेंट)हुआ था जिसमें सर्वे नंबर 86/1/1/1/1/ 22-हेक्टेयर की भूमि में से सेटलमेंट के समय दो नंबर जारी किए गए थे जिसमें खसरा पाचशाला कॉलम नंबर 1 पर सर्वे नंबर 110 जारी होते हुए कूल भूमि 19-891- रास्ता मद और सर्वे नंबर 105 आबादी आवास योजना खसरा पाचशाला में दर्ज कुल भूमि 1-012- और अधिकार अभिलेख में कूल भूमि 1-013 दर्ज थी खसरा पाचशाला और अधिकार अभिलेख में अंतर होते हुए दर्ज थी जिसके बाद में लगातार वर्ष 1984-85 तक अक्कू रामा सगजी द्वारा संबंधित भूमि पर अतिक्रमण कर रखा था और सरकारी संपत्ति को ओने पौने दामों में भू माफियाओं को वर्ष 1990 के बाद में बैच दिया गया सबसे बड़ा सवाल वर्ष 1958-59 से लेकर लगातार वर्ष 1985 -86 22 हेक्टेयर जिसका वर्तमान सर्वे नंबर 110 और 105 की भूमि जो शासन की थी उस पर वर्तमान में इन व्यक्तियों का कब्जा कैसे हो गया और इनके द्वारा भूमाफिया को कैसे बैच दिया गया है और संबंधित सरकारी भूमियों पर रजिस्ट्री कैसे हो गई भ्रष्टाचार मामले में राजस्व अधिकारियों पर बड़ा उठ रहा है वर्तमान में देखा जाए तो लाखों रुपए की बेशकीमती शासन की भूमि पर वर्तमान में धड़ल्ले से निर्माण कार्य चल रहा है जिसको रोकना कहीं न कहीं वर्तमान अनुविभागीय अधिकारी पेटलावद के लिए एक चुनौती जैसा प्रतीत होता देख रहा है।

शिकायत के बाद भी नही रुका काम

ग्राम बामनिया निवासी श्रवण मॉलवीय ने मामले अनुविभागीय अधिकारी पेटलावद को लिखित शिकायत दर्ज करवाते हुवे ,पुराने रेकॉर्ड के साथ अवगत करवाया की नगर में शासकीय सर्वे नंबर की भूमि 104,105, और 106 को रेकॉर्ड में हेराफेरी कर बेचा गया और उस पर निर्माण किया जा रहा है जिसको रोक कर मामले की जांच की जाए । शिकायत के बाद अनुविभागीय अधिकारी ने 16 दिसम्बर को तहसीलदार पेटलावद को जांच के लिए लिख दिया लेकिन तहसीलदार द्वारा न तो जांच शुरू की गई न ही कार्य रोका गया । शिकायतकर्ता श्रवण मॉलवीय ने बताया कि भूमि के सम्बंध में पूरा रिकॉर्ड मेरे पास उपलब्ध है जो प्रमाणित होकर राजस्व की नकल शाखा से निकाला गया है और उसके अनुसार बड़ी हेरा-फेरी का मामला सामने आ रहा है।

सरस्वती शिशु मंदिर का वार्षिकोत्सव कार्यक्रम सम्पन्न

माही की गूंज, खरगोन/बमनाला।

सरस्वती शिशु मंदिर बमनाला में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत दूसरे दिन नन्हे-मुन्ने भैया बहनों के रंगारंग कार्यक्रम संपन्न हुए। जिसमें सरस्वती वंदना, स्वागत नृत्य, लोक नृत्य, देशभक्ति गीत, नुक्कड़ नाटक (नशा मुक्ति पर नाटिका) सर्जिकल स्ट्राइक का मंचन शिशु वर्ग द्वारा विद्यार्थियों की शैक्षणिक समस्या के विषय को लेकर कव्वाली तथा अनेक आने प्रस्तुतियाँ दी गई।

कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खंड कार्यवाहक दिनेश बापना और मातृशक्ति की जिला संयोजिका श्रीमती सरिता बापना उपस्थित रहे अध्यक्ष श्रीमती ममता सवनेर, भगवानसिंह गिन्नारे, जगदीश सिंह चौहान एवं रामसिंह पटेल श्रीराम शिक्षा समिति के स्थापना सदस्य के रूप में मंचासीन रहे। अतिथियों का स्वागत केदार सोहनी, प्राचार्य सुबोध परचुरे, अतीश अग्रवाल ने किया।

इस अवसर पर दिनेश बापना ने बताया कि, वे भी सरस्वती शिशु मंदिर के पूर्व छात्र रहे हैं। मैंने शिक्षा भले ही शहरों से प्राप्त की है किंतु संस्कार सरस्वती शिशु मंदिर से ही प्राप्त कि है। जरूरी नहीं कि अच्छी शिक्षा के लिए शहरों की ओर ही भागा जाए, छोटे गांव के विद्यालयों से भी भैया बहनों की प्रतिभा का उन्नयन और विकास हो सकता है।

इस अवसर पर अभिभावकों के अतिरिक्त कार्यक्रम में बमनाला और आसपास के क्षेत्र के आमजन काफी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन सुरेश कुमरावत, श्रीमती अर्चना जोशी दीदी, सुश्री. कल्पना गोले दीदी, कु. दीपाली यादव, कु. रानी वर्मा और भैया सुमित सोलंकी ने किया। कार्यक्रम के अंत में आभार प्रदर्शन इंद्रपालसिंह गिन्नारे ने किया। समस्त आचार्य परिवार भैया- बहनों के अथक परिश्रम और उत्साह के फलस्वरूप एक श्रेष्ठ स्तर का कार्यक्रम देर रात्रि में संपन्न हुआ। वार्षिकोत्सव के समापन के तीसरे और अंतिम दिन सहभोज का आयोजन रखा गया। जिसमें विद्यालय के भैय्या बहनों के साथ समस्त विद्यालय परिवार, समिति सदस्य, पत्रकार बंधु और नगर के गणमान्य लोग सहभोज में उपस्थित रहे।

वाह विधायक जी मौज कर दी ...

सरकार में रहते जिस स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर को बीएमओ बनाया वहां आज तक नहीं पहुँचा डॉक्टर

माही की गूंज, पेटलावद।

क्षेत्र के विधायक वालसिंह मैडा जो विगत चार साल जनता से दूर रहे अचानक मीडिया की सुर्खियों में आने के लिये कही भी पहुँच कर मीडिया कवरेज ले रहे हैं और लोगो को हो रही परेशानीयो के लिए आवाज़ उठाने की बात कर रहे है। जिन परेशानीयो से लोग जूझ रहे हैं वो नई है लेकिन चुनावी बुखार ने विधायक साहब को अचानक लोगो की परेशानीया दिखा दी। विगत दिनों रायपुरिया के प्रा.स्वा. केंद्र में डॉ. की कमी को लेकर अस्पताल का दौरा किया और डॉक्टर को पदस्थ करवाने के लिए जनता को आश्वासन दिया। जबकि रायपुरिया ही नही बल्कि विकास खण्ड के ज्यादातर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आये दिन आवाज़ उठ रही है। पेटलावद में पदस्थ ज्यादातर डॉक्टर अपनी निजी प्रैक्टिस पर ज्यादा रहते हैं। कई बार शिकायत के साथ-साथ हॉस्पिटल की ड्यूटी के समय खाली पड़ी कुर्सियों के फोटो सहित खबरे प्रकाशित हो चुकी हैं, सिविल हॉस्पिटल जैसे बड़े हॉस्पिटल में स्टॉफ की कमी और लापरवाही सहित इलाज के नाम और पैसे वसूलने के मामले सामने आ चुके हैं। पर विधायक साहब ने कभी इसकी सूद नही ली, चुनाव को देखते हुए मैदान में उतरते दिख रहे है।

आज तक नही है डॉक्टर

विधानसभा चुनाव 2018 के चुनाव में जीत मिलने के बाद 15 माह की कांग्रेस सरकार रही इस दौरान विकास खण्ड की झकनावदा पंचायत के प्रा.स्वा. केंद्र में पदस्थ डॉ. एमएल चोपड़ा को विधायक साहब की अनुशंसा से बीएमओ बना दिया गया था। तब से लेकर आज तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र झकनावदा में किसी डॉ. को पदस्थ नही किया गया। बीएमओ खुद वहां आज तक पदस्थ है लेकिन अधिकारी का पद मिलने के बाद से झकनावदा की जनता सहित क्षेत्र को लगने वाले 50गाँव के लोगो को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए राजगढ़ और सरदारपुर जाना पड़ रहा है।

शहरी स्वास्थ्य केंद्र की मांग भी नहीं कर पाए

ऐसे ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पेटलावद को तीन किलोमीटर दूर सिविल हॉस्पिटल बन जाने से नगर की स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ चुकी। छोटे-मोटे इलाज के लिए लोगो को तीन किलोमीटर दूर जाना पड़ता हौ शाम होने के बाद सिविल हॉस्पिटल पहुँचने के लिए कोई साधन नही है। माही की गूंज ने मुद्दा उठाया था और विधायक साहब से बात की तो उन्होंने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से शहरी प्रा.स्वा. केंद्र पुराने स्थान पर शुरू करने की मांग करने की बात कही थी, लेकिन आज तक उनकी और से कोई मांग नही की गई।

हर मामले को विधानसभा में उठाने की बात, आज तक एक सवाल नही

विधायक साहब की नाक के नीचे भाजपा सरकार के कई भ्रष्टाचार सामने आ चुके हैं। खेल सामग्री घोटाला, साड़ी घोटाला, सहित कई बड़े मामले सामने आए थे। कई मामलों में विधायक साहब जब भी मीडिया के सामने आते हैं, विधानसभा में मामला उठाने की बात करते हैं। लेकिन वर्तमान में जब विधानसभा का रिकॉर्ड आया तो पता चला कि, कोई भी प्रश्न विधायक वालसिंह मैडा की और से विधानसभा में नही लगाया गया। विगत दिनों विधानसभा क्षेत्र के खुद के रामा ब्लॉक में नल-जल योजना में लापरवाही करने पर ठेकेदार ओर प्रशासन को चुनौती दे रहे थे। वही पेटलावद विकास खण्ड की ग्राम पंचायत झकनावदा की नल-जल योजना का कार्य अधूरा छोड़ कर ठेकेदार चला गया। पेटलावद, बामनिया सहित ग्रामीण इलाकों में नल-जल योजना में हुए कार्यों में भारी लापरवाही हुई। लेकिन विधायक साहब की आवाज़ नही निकली। भाजपा नेता अजय जैन ने कहा है कि, कांग्रेस विधायक वालसिंह मैडा प्रचार पसार पाने के लिए कुछ भी बोलते हैं।

जैन तीर्थ सम्मेदशिखर जी को पर्यटन स्थल बनाने का हुआ सभी दूर विरोध

पेटलावद

सकल जैन समाज के चारो पंथ के हजारों समाजजनों ने विशाल विरोध रैली निकाली

माही की गूंज, झाबुआ।

भारत के प्रसिद्ध जैन तीर्थ श्री सम्मेद षिखरजी तीर्थ, जो देश के समग्र जैन समाज की आस्था एवं श्रद्धा का अटूट केंद्र है, जहां असंख्य जैन मुनियों एवं साधु-साध्वी भगवंतों ने जत-तप, आराधना करते हुए हुए मोक्ष सिधारे है। देश सहित विदेशों से भी प्रतिवर्ष लाखों लोग इस तीर्थ पर दर्शन के लिए पहुंचते है। उक्त तीर्थ को झारखंड की गठबंधन सरकार द्वारा पर्यटन स्थल के रूप में घोषणा से संपूर्ण भारत का जैन समाज अत्यंत ही नाराज एवं आक्रोषित है। चहू ओर से बस एक ही मांग उठ रहीं है कि जैन तपोभूमि श्री सिम्मेद शिखरजी तीर्थ को पर्यटन स्थल के रूप में घोषित नहीं किया जाए, इसे ऐतिहासिक समय में चल आ रहे नाम ''जैन महातीर्थ'' ही रहने दिया जाए।

झाबुआ जिले सहित जिला मुख्यालय झाबुआ पर भी सकल जैन समाज, जिसमें श्री श्वेतांबर मूर्तिपूजक संघ, स्थानकवासी श्री संघ, तेरापंथ महासभा एवं दिगंबर जैन समाज और समस्त जैन संगठनों ने मिलकर इस बंद को पूरी तरफ सफल बनाया एवं श्री सम्मेद षिखरजी तीर्थ को पर्यटन स्थल नहीं बनाने की मांग पूरी तरह बुलंदी और ताकत के साथ रखी गई। जिसके अंतर्गत समाजजनों ने बुधवार को आधे दिन अपने प्रतिष्ठान बंद रखने के साथ इस दिन समाज के लोग शासकीय कार्यों से भी स्वच्छैविक रूप से विरत रहे और दोपहर में समर्ग्र जैन समाज की महारैली में शामिल होने के साथ कलेक्टोरेट पहुंचकर हजारों समाजजनों ने सरकार के इस फैसले पर तीव्र विरोध जताया। बाद यहां चारो पंथ के समाज अध्यक्षों की ओर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदि के नाम अपर कलेक्टर एसएस मुजाल्दा को ज्ञापन सौंपा गया।

बुधवार अलसुबह से ही सकल जैन समाज के लोगों ने अपने-अपने प्रतिष्ठान बंद रखने के साथ शासकीय कार्यों से स्वैच्छिक विरत रहे। दोपहर 1.30 बजे से समाजजन राजवाड़ा पर एकत्रित हुए और यहां निर्धारित समय दोपहर ठीक 2 बजे 2-2 की कतार में चारो पंथ के हजारों महिला-पुरूष हाथों में सरकार के फैसले के विरोध की तख्तीयां लेते हुए शामिल हुए। चार पंथ के समाज अध्यक्षों एवं विभिन्न जैन संगठनों ने नेतृत्व प्रदान किया। यहां श्री श्वेतांबर जैन श्री संघ अध्यक्ष मनोहरलाल भंडारी, स्थानकवासी श्री संघ अध्यक्ष प्रदीप रूनवाल, तेरापंथ महासंघ से प्रभारी अध्यक्ष कैलाषचन्द्र श्रीमाल, दिगंबर जैन समाज अध्यक्ष निलेष शाह आदि के साथ जैन संगठनों के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री, केंद्रीय पर्यटन मंत्री एवं झारखंड के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन अपर कलेक्टर श्री मुजाल्दा को सौंपा।

झाबुआ

माही की गूंज, बामनिया।

झारखंड जिले के गिरिडीह जिले में सम्मेदशिखर जी तीर्थ है ये वह स्थल है जहाँ 24 तीर्थंकर भगवान में 20 तीर्थंकरो को मोक्ष प्राप्त हुआ था केंद्रीय वन मंत्रालय ने जैन तीर्थ स्थल को वन्य जीव अभ्यारण्य हिस्सा बनाने के साथ पर्यावरण पर्यटन स्थल की अनुमति प्रदान की है जिसके विरोद्ध में सकल जैन समाज के साथ सभी ग्राम के समाज जानो ने विरोध स्वरूप सभी ग्राम वासियो ने अपनी दुकानों को बंद रख कर व विरोध रैली निकाल कर बामनिया पुलिस चौकी में महामहिम राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है।

माही की गूंज, थांदला

शालीन जैन समाज ने अपना विरोध दर्ज करवाते हुए पूरे भारत बन्द का आह्वान किया गया। जिसके फल स्वरूप थांदला नगर में स्थानकवासी जैन समाज के वरिष्ठ नगीनलाल शाहजी, अध्यक्ष जितेंद्र घोड़ावत, दिगम्बर समाज के अध्यक्ष अरुण कोठारी, श्वेताम्बर मूर्तिपूजक संघ अध्यक्ष कमलेश दायजी, तेरापंथ सभा अध्यक्ष अरविंद रुनवाल के नेतृत्व में सकल जैन समाज ने अपने व्यापार बन्द रख कर विशाल रैली का आयोजन किया। रैली में पुरुषों के अलावा पहली बार महिलाओं व बच्चों ने भी शामिल होकर सोरेन सरकार व केंद्र सरकार के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त हुए जमकर नारे बाजी की। रैली आजाद चौक से प्रारंभ हुई जो नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुँची जहाँ सकल संघ ने एकता का परिचय देते हुए जैन समाज के तीर्थ को बचाने व उपद्रवियों पर कार्यवाही करने की अपील की व ज्ञापन दिया।

रायपुरिया

माही की गूंज, रायपुरिया

स्थानकवासी जैन समाज , दिगम्बर समाज , श्वेताम्बर मूर्तिपूजक, तेरापंथ सभा अखिल भारतीय राजेंद्र जैन युवा परिषद, नवयुवक मंडल, अरिहंत ग्रुप नेतृत्व में सकल जैन समाज ने अपने व्यापार बन्द रख कर विशाल रैली का आयोजन किया। रैली में पुरुषों के अलावा पहली बार महिलाओं व बच्चों ने भी शामिल होकर सोरेन सरकार व केंद्र सरकार के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए जमकर नारे बाजी की। रैली भगवान श्री सुमित नाथ जी जैन मंदिर से प्रारंभ हुई जो नगर के मुख्य मार्ग से होती हुई पुलिस थाना पहुँची जहाँ सकल संघ ने एकता का परिचय देते हुए जैन समाज के तीर्थ को बचाने व उपद्रवियों पर कार्यवाही करने की अपील की। सकल जैन समाज ने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री एवं झारखंड मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया।

माही की गूंज ,पेटलावद

पवित्र सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाने के विरोध में 21 दिसम्बर को भारत बंद के साथ पेटलावद भी बंद रहा। पेटलावद नगर के पेट्रोल पंप भी बंद रहे। इस आंदोलन को सोनी समाज ने भी समर्थन देकर अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। इस बंद में स्थानकवासी तेरापंथी श्वेतांबर मंदिर मार्गी ,दिगंबर समाज के अलावा सभी समुदाय के युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी ने काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया।

बामनिया

थांदला

बगुलों से परेशान प्रशासन तथा आम जन, हरे भरे पेड़ काटने को हो रहे मजबूर

जिन्हे जंगल में रहना चाहिए था वे कस्बे में आ बसे

माही की गूंज, आम्बुआ।

प्राकृतिक नियमानुसार आबादी क्षेत्र में मानव तथा वन्य क्षेत्र में वन्यजीवों को रहना चाहिए मगर देखा जा रहा है कि, कई वन्यजीव आबादी क्षेत्र में आ बसते हैं। उन्हीं में बगुला पक्षी भी शामिल है। यह आबादी क्षेत्र में स्थित पेड़ों पर डेरा जमा कर वहां का वातावरण प्रदूषित करता है। जिस कारण पेड़ या तो स्वयं सूख जाते हैं या फिर उन्हें काटना छांटना पड़ जाता है।

बगुला जो की नदी तालाबों के किनारे रहकर जलीय जीव जंतुओं को खाकर अपना पेट भरता है। इसे जंगली क्षेत्र में जलाशयों के आसपास स्थित पेड़ों पर बसेरा करना चाहिए, मगर देखा जा रहा है कि यह बगुले सुबह होते ही जंगलों की ओर उड़ जाते हैं तथा शाम होते-होते कस्बा- बाजार और शहरों की ओर आकर पेड़ों पर रैन बसेरा करते हैं। यहीं रहकर घोसले बनाकर अंडे देकर बच्चे निकालते हैं। अधिक संख्या में पेड़ों पर रहने से इनकी ÷बीट÷ से संपूर्ण क्षेत्र बदबूदार होकर प्रदूषण फैलाते हैं। यह जहां जिस पेड़ पर रहते हैं आस-पास रहने वाले परेशान हो जाते हैं। इनकी ÷बीट÷ से कई बार हरे भरे पेड़ सूख जाते हैं या फिर मजबूरी में लोग पेड़ों की कटाई-छटाई कर देते है, ताकि यह यहां आसरा न बना सके। पेड़ों की कटाई से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है पर गंदगी के कारण पेड़ों को काटना-छांटना भी मजबूरी कही जा सकती है। आम्बुआ में पंचायत प्रांगण क्षेत्र हो या कस्बे में आवासीय क्षेत्र हो यह बगुले दिखाई दे जाएंगे इनके निवास के कारण पेड़ तथा जमीन सफेद चूने की तरह दिखाई देती है। एक बार जिस पेड़ पर इनका डेरा जम गया तो बमुश्किल इन्हें हटाया जा सकता है।

ग्राम पंचायत आम्बुआ सरपंच रमेश रावत ने बताया कि, पंचायत क्षेत्र में तीन-चार पेड़ों पर बगुले रहकर गंदगी फैला रहे हैं। जिस कारण दुर्गंध से सब परेशान हो रहे हैं। मजबूरन पेड़ों की कटाई करना पड़ रही है।

कंटेनर ने मोटरसाइकिल सवार युवकों को टक्कर मारी, एक की मौत, तीन घायल

माही की गूंज, नानपुर।

जिले के नानपुर थाना अंतर्गत मंगलवार-बुधवार रात में कंटेनर क्रमांक आरजे 09 जीसी 3672 और बाइक क्रमांक एमपी 69 एमसी 3957 सवार की टक्कर में चार युवकों के दबने से तीन गंभीर घायल हो गए, जबकि एक की घटनास्थल पर ही दबने से मौत हो गई।

नानपुर पुलिस थाने के सामने तेज गति से आ रहे 20 टायर के कंटेनर ने खंडवा-बड़ौदा रोड पर पुलिस थाने के सामने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी। चार युवक पेट्रोल भरने के लिए जा रहे थे तभी हादसा हुआ। दुर्घटना से इस मार्ग की बिगड़ी ट्रैफिक व्यवस्था से आम जन परेशान रहे।

पुलिस थाने के सामने से रोजाना अवैध रूप से बेधड़क अवैध कारोबार हो रहा है जिसमे अवेध वसूली होने से वाहन चालक भी परेशान रहते है। कभी भी किसी पर कारवाई नही होने से ग्रामीणों में आक्रोश बना रहता है। जब कि जिले में 17वा यातायात सप्ताह मनाया जा रहा है। जिसके बाद भी वाहन चालक खुले आम यातायात नियमो की धज्जियां उड़ा रहे है।

दुर्घटना के बाद तीन युवकों में से दो युवकों को गुजरात के बड़ौदा रेफर किया गया। वही दुर्घटना में विकास पिता तेरसिह की मौत हो गई। प्रताप पिता दुलेसिंह की हालत गम्भीर थी। सचिन पिता मन्तर, भारत पिता रतन सिह के कंटेनर में दबने से उन्हें निकालने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जेसीबी व प्रोकलेन से कंटेनर को हटाए जाने तक तीन युवक दबे रहे। ट्राफिक भी जाम हो रहा। वही बिजली के पोल टूटने से बिजली भी बंद की गई थी। ग्रामीणों व पुलिस जवानों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पहुचाया गया। घटनास्थल पर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो रहा था। सभी चारो युवक मोरासा के एक ही परिवार के बताए जा रहे है।

गैस सिलेंडर के भाव बढ़ने से परेशान समूह लकड़ी पर बना रहे भोजन

माही की गूंज, आम्बुआ।

महंगाई का असर सभी और बड़ता नजर आ रहा है। इसका एक असर घर तथा अन्य स्थानों पर बने रसोईघर में अधिक दिखाई दे रहा है। उज्जवला योजना में निःशुल्क मिला सिलेंडर अब नहीं भरा पाने के कारण पुनः चूल्हा भट्टी में लकड़ी का उपयोग होने लगा है।

गूंज संवाददाता को मिली जानकारी के अनुसार शिक्षण संस्थाओं में मध्यान्ह भोजन बनाए जाने का कार्य स्वसहायता समूहों द्वारा किया जा रहा है। कस्बा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत समूहों को भी गैस सिलेंडर प्रदाय किए गए हैं। जिस संस्था में 200-300 बच्चों के लिए भोजन बनता है वहां एक सिलेंडर एक हफ्ते चलता है। इस तरह पूरे महीने में लगभग 5 सिलेंडर लगते हैं। एक सिलेंडर भरवाने में क्षेत्र में एक हजार 150 रुपए कीमत लग रही है। यहां भोजन बनाने वाले समूह इतना महंगा सिलेंडर नहीं खरीद पा रहे हैं। मजबूरन उन्हें लकड़ी जलाना पड़ रही है। जिस कारण इतना धुआं होता है कि, कमरे तो काले हो ही रहे हैं आंखों से आंसू भी बहते हैं फेफड़ों में जाने वाला धुआं भोजन बनाने वाली चार-पांच महिलाओं के स्वास्थ पर विपरीत असर डाल रहा होगा।

समूह की महिलाओं ने बताया कि, सिलेंडर के भाव बढ़ने के कारण समूह इतनी राशि खर्च नहीं कर सकता। मजबूरन चूल्हे में लकड़ी जलाना पड़ती है। गैस से लकड़ी सस्ती पड़ती है फिर यह लकड़ी का धुआं भले ही उन्हें बीमारी की ओर धकेल दे। शासन की ओर से सब्सिडी भी लगभग बंद कर दी है। यदि मिल भी रही है तो बहुत कम मिलती है। कई बार सब्सिडी खातों में नहीं आती है। शासन-प्रशासन को इस ओर अविलंब ध्यान देकर मध्य भोजन बनाने वाले समूह को सिलेंडर के भाव में कमी करना जरूरी माना जा रहा है।

आशुतोष 13 वर्ष की उम्र में बन गया जिले का स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर

कटनी।

सरकार की कई योजनाओं के लिए अलग-अलग ब्रांड एंबेसडर का नाम आपने तो सुने होंगे, इसी तरह मध्य प्रदेश के कटनी जिले के आशुतोष मानके को भी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना का ब्रांड एंबेसडर बनाया गया है। आशुतोष मानके में खास बात ये है कि, उनकी उम्र महज 13 वर्ष है और इस उम्र में उन्हें कटनी जिले का 'स्वच्छ भारत मिशन' का एंबेसडर बना दिया गया है।

दरअसल, आशुतोष मानके ने स्वच्छता और कूड़े के निपटारे को लेकर कटनी जिले के कलेक्टर अवि प्रसाद को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में आशुतोष ने कूड़े के प्रबंधन और उसके निपटारे को लेकर कई अच्छी सलाह दी थी। पत्र को पढ़ने के बाद जिला कलेक्टर अवि प्रसाद प्रभावित हो गए और आशुतोष को मिलने के लिए ऑफिस बुलाया और कटनी जिले का स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड एंबेसडर बना दिया।

कौन हैं आशुतोष...?

आशुतोष मानके कटनी के रहने वाले हैं। सीएम राइस मॉडल स्कूल में 9वीं कक्षा के छात्र हैं। इन सबसे अलग आशुतोष की अब एक अलग पहचान भी बन गई है। अब आशुतोष कटनी जिले के लिए 'स्वच्छ भारत मिशन' के ब्रांड एंबेसडर भी बना दिए गए हैं। कलेक्टर के इस निर्णय के बाद आशुतोष काफी खुश हैं और उनकी बहन आयुषी मानके ने कहा कि, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि, कलेक्टर सर इतनी जल्दी उनके पोस्टकार्ड का जवाब देंगे।

कटनी के जिला कलेक्टर अवि प्रसाद ने बताया कि, उन्हें ऑफिस के टेबल पर आशुतोष का लेटर मिला था जिसको पढ़ने के बाद उन्होंने आशुतोष को ऑफिस बुलाया। उन्होंने कहा कि, जब मैंने आशुतोष की दी गई सलाह को पढ़ा, मैं उस लेटर के लिखने वाले से मिलना चाह रहा था, उससे मिलने के बाद मुझे समझ आया कि आशुतोष काफी प्रतिभावान है और मैंने निर्णय लिया कि उसे जिले का स्वच्छता एंबेसडर बना दिया जाए।

2 वर्ष के बालक की मौत के बाद घर वालों ने दान की आंखें

पिता ने कहा, तसल्ली है उसकी आंखों दो लोग को रोशनी देगी

माही की गूंज, इंदौर।

कहा जाता है कि जिंदगी में कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे दूसरे लोगों जिंदगी बेहतर बन सके और मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के रहने वाले अक्षज ने मरने बाद वो कर है। अब उनकी आंखें दो लोगों की जिंदगी में उजाला करेंगी। इंदौर में दो वर्ष के अक्षज की अनुवांशिक बीमारी से मौत हो गई थी। अक्षज की मौत के बाद परिवार वालों ने उनकी दोनों आंखों को दान करने का निर्णय लिया था। अब अक्षज की मृत्यु के बाद आंखे दो जरूरतमंदों को प्रत्यारोपित की जाएंगी। जिससे दोनों लोगों की जिंदगी में रोशनी आएगी।

इंदौर शहर के शासकीय अस्पताल, महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय (एमव्हायएक) के एक अधिकारी ने बताया कि, अक्षज की किसी आनुवांशिक बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई थी जिसके बाद उसके परिवार वलों ने ये मिशाल पेश करने वाला फैसला लिया है। अधिकारी ने बताया कि, अक्षज बांके टायरोसिनेमिया नाम जन्मजात बीमारी से जूझ रहा था। सोमवार को इलाज के दौरान एमव्हायएक अस्पताल में उसकी मौत हो गई है। जिसके बाद परिवार वालों ने नेत्रदान करने की इच्छा जाहिर की थी। अब दोनों आंखों को दो अलग-अलग लोगों में प्रत्यारोपित किया जाएगा।

इकलौता चिराग था अक्षज

इस दुख की घड़ी में इस तरह का फैसला लेना साहसिक काम है। अक्षज के पिता एक निजी विद्यालय में शिक्षक हैं। उन्होंने बताया कि, अक्षज घर का इकलौता लड़का था। अपने बच्चे की आंखों को दान करने के फैसले के बारे में पिता ने कहा कि, मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे इस बात की तसल्ली है कि उसकी आंखों से दो लोग दुनिया देख सकेंगे।

जैन समाजजनों ने रैली निकालकर सौंपा ज्ञापन

माही की गूंज, जोबट।

जैन धर्म के झारखण्ड के गिरिडिह जिले के मधुबन में स्थित तीर्थ स्थल सम्मेद शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में जैन समाज द्वारा रैली निकालकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान समाजजन रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए ज्ञापन देने पहुंचे। रैली के दौरान 'झारखंड सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी' के नारे लगाए। रैली नगर के प्रमुख मार्गो से होती हुई एसडीएम कार्यालय पहुंची। जिसके बाद शाम 4 बजे जिला मुख्यालय पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया।

हाई स्कूल में आखिर क्या चल रहा है झोल, फर्जी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति का मामला

माही की गूंज, पेटलावद।

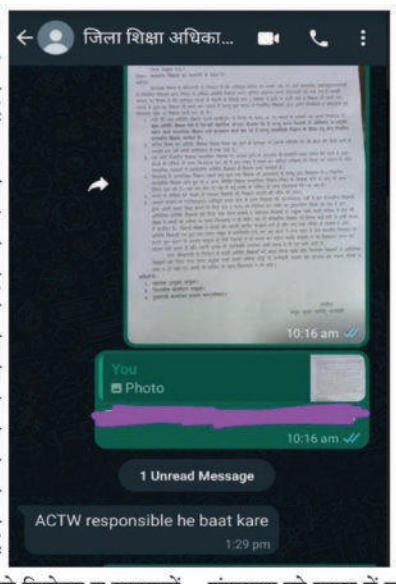

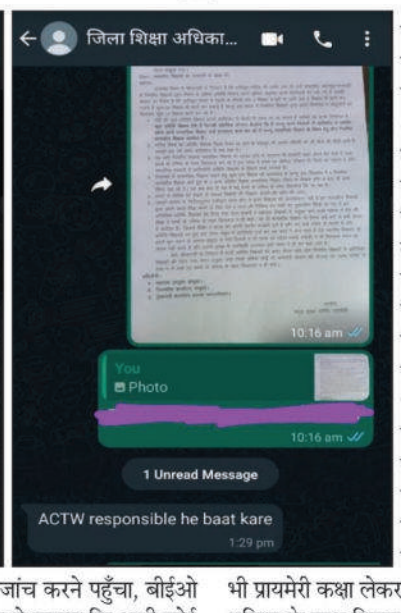

एकीकृत पोर्टल पर नम्बर 174 पर दर्ज शासकीय हाईस्कूल, तारखेड़ी में नियमित शिक्षकों द्वारा नियम से अधिक अतिथि शिक्षक अपने सुविधा अनुसार अपने रिश्तेदारों को रखे गये है जबकी शासन का नियम है कि एकीकृत शाला में पहली से पाचवी तक 3 शिक्षक व 6टी से 10वी तक 6 शिक्षक ही कार्य कर सकते है कुल 09 शिक्षक ही कार्य कर सकते है परन्तु इस शाला में नियमित शिक्षकों द्वारा अपने रिश्तेदार व चादूकारों को मिलाकर कुल 13 शिक्षक कार्य कर रहे है । मामले की शिकायत ग्रामीणों ने मोबाइल व्हाट्सब के माध्यम से आवेंदन भेज कर की है फिलहाल कोई शिकायतकर्ता खुल कर सामने नही आया लेकिन शिकायत के बाद विभाग की हलचल देख पता चल रहा है कि मामला बड़ा है , अधिकारी की जानकारी होने के बाद भी विकास खण्ड के अधिकारी शिकायत से खुद को अंजान बन रहे हैं जबकि बीआरसी कार्यालय पेटलावद का बाबू मंगलवार को स्कूल में जांच करने पहुँचा, बीईओ पेटलावद आर के यादव ने बताया कि अभी कोई शिकायत हुई इसकी जानकारी नही है लेकिन पूर्व में हुई शिकायत को लेकर बाबू को जांच कहा था ।

ये है मामला

आवेंदन में लिखी शिकायत के अनुसार ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में कुछ अतिथि शिक्षक इनके आशीर्वाद से किसी भी समय आ जा सकते है क्योंकी वह इनके रिश्तेदार है, कुछ अतिथि शिक्षक ऐसे है जिनकी शेक्षणिक योग्यता बी.कॉम कि है परन्तु अपने पिताजी के आशिर्वाद से अतिथि स्कोर कार्ड सामाजिक विज्ञान दर्ज करवाकर कार्य कर रहे है परन्तु सामाजिक विज्ञान के विषय हेतु तीन नियमित शासकीय शिक्षक कार्यरत है। गणित विषय का अतिथि शिक्षक जिला पैनल का होने के बावजूद भी अपनी भतिजी जो की बी.ई की डीग्री धारी है ,उसको इस वर्ष अपने आशिर्वाद से रख रखा है ।सभी नियमित शिक्षक माध्यमिक शिक्षक पर पदस्थ होने के उपरान्त भी प्रायमेरी कक्षा लेकर बैठे रहते है तथा बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे है इस संबंध में बच्चों का भौतिक परीक्षण भी किया जा सकता है और माध्यमिक कक्षाओं में आशिर्वादी अतिथि शिक्षकों से शिक्षण कार्य करवाते है । शिकायकर्ताओ का कहना है कि शासन के निर्देशानुसार एकीकृत शाला होन से इतने शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है। शिकायतकर्ताओ का कहना है कि स्कूल में भारी लापरवाही के साथ भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा हैं।

सागवान के पेड़ काट पर्यावरण को पहुंचाया नुकसान, भरपाई के नाम पर कुछ नहीं

मामला उजागर होने के बाद भी आंखे मूंदे बैठे वन विभाग व पंचायत के जिम्मेदार

माही की गूंज, पेटलावद/अमरगढ़।

करीब 10 दिन पूर्व ग्राम पंचायत अंतर्गत रेलवे स्टेशन के समीप कृषि भूमि खसरा नम्बर 43 में 15 सागवान के पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर दी गई थी। जिसका पूरा मामला उजागर होने के लगभग 10-12 दिन बाद भी न तो वन विभाग व न ही ग्राम पंचायत का कोई जिम्मेदार उक्त स्थान पर पहुंचा न ही कोई कार्रवाई हुई। जो कि वन विभाग व पंचायत पर कई प्रश्न चिन्ह खड़े कर रही है। उक्त सागवान के पेड़ों को काटने के बाद उसी स्थान पर छोड़ दिया गया था जो आज भी वही अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहे है। बता दे कि, सागवान के पेड़ों को काटने के पूर्व परमिशन की आवश्यकता होती है साथ ही ग्राम पंचायत की परिधि से बाहर ले जाने हेतु परिवहन की परमिशन की भी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन उक्त मामले में न तो काटने की परमिशन ली गई है, न ही परिवहन की परमिशन ली गई है। मामले को माही की गूंज द्वारा प्रमुखता से प्रकाशित किया लेकिन खबर के 08 दिन बाद तक वन विभाग न ही राजस्व विभाग की नींद खुली और मौके पर जांच तक नही पहुँचे।

थांदला-पेटलावद बिट में उलझा मामला

वन विभाग की राजस्व सीमा को लेकर मामला उलझ गया है, अमरगढ़ ग्राम पेटलावद विकास खण्ड की राजस्व सीमा में आता है जबकि वन विभाग के अनुसार अमरगढ़ गाव थांदला वन विभाग में आता है, बामनिया क्षेत्र के बिट प्रभारी धीरज गुर्जर ने बताया कि अमरगढ़ बिट थांदला वन विभाग में पड़ता है और इसकी जानकारी थांदला वन विभाग को दे दी गई है वही थांदला वन विभाग के रेंजर पटेल साहब का कहना है कि जिस भूमि पर पेड़ काटे गए हैं वो वन क्षेत्र की भूमि नही है वो पेटलावद राजस्व क्षेत्र की भूमि है इस पर कार्यवाही का अधिकार एसडीएम पेटलावद को आता है जब वृक्षों के संरक्षण और बचाओ का हवाला देकर जिम्मेदारी का अहसास करवाया गया तो साहब के सुर बदले और कहा कि मौका पटवारी के साथ देख कर पंचनामा बना कर आगे की कार्यवाही के लिए एसडीएम की और भेज देंगे, वही राजस्व विभाग पेटलावद की ओर से कोई कार्यवाही इस मामले नही की।

महिला बाल विकास विभाग में हुए साड़ी सप्लाई घोटाले की जांच को दबाकर किया जा रहा रफा-दफा

सूचना अधिकार में नही दिए जा रहे जांच के प्रमाणित दस्तावेज, संभागीय आयुक्त के बाबू बता रहे हैं जादू

जिले भर में हुआ झोल, सप्लाई के पीछे सत्ताधारी नेताओं का हाथ इसलिए दबाया जा रहा है मामला

माही की गूंज, पेटलावद, राकेश गेहलोत।

महिला एवं बाल विकास कार्यालय पेटलावद में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को शासन की और से दी जाने वाली साड़ी में घोटाले का मामला कुछ समय पूर्व सामने आया था। मामले को मीडिया द्वारा उठाने के बाद पूर्व कलेक्टर द्वारा मामले की जांच के आदेश देकर जांच समिति बनाई थी। पूर्व अपर कलेक्टर और महिला बाल विकास के जिला प्रभारी अभय खराड़ी द्वारा मामले की जांच करवाई थी, जिंसमे महिला बाल विकास अधिकारी इशिता मसानिया सहित क्षेत्र की सुपरवाइजर और आंगनवाडी कार्यकर्ता, सहायकाओ के बयान दर्ज किए गए थे। जांच में भारी लापरवाही सामने आई थी और सम्बंधित सुपरवाइजर को निलंबित किया गया था। साथ ही महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी इशिता मसानिया पर कार्रवाई के लिए संभागीय आयुक्त की अनुसंशा के लिए भेजा गया था जिस पर आज दिन तक कोई कार्रवाई नही हुई है।

यह था मामला

शासन की और से जिले भर की सभी आंगनवाडी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओ को दो साड़ी के लिए 800 रुपये खाते में डाले गए थे लेकिन सप्लायरों ने सभी विकास खंडों में अपने-अपने हिसाब से सेटिंग जमाकर एक ही व्यक्ति से घटिया साड़ियां तय कर सभी आंगनवाडी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओ को सुपरवाइजर के माध्यम से दे दी। वही उसका भुगतान 800 रुपये सुपरवाइजर ने वसूल कर सप्लायर को दे दिये। जिंसमे कमीशन की बंदरबाट हुई, सप्लाई की गई साड़ियां बेहत ही हल्की ओर मात्र 150-200 रुपये की कीमत की थी। मामले की शिकायत के बाद जांच हुई। जिंसमे पूरा घोटाला सामने आया और दोषियों पर कार्रवाई की अनुशंसा की गई। पेटलावद महिला परियोजना अधिकारी इशिता मसानिया भी इस मामले में जांच में कही न कही शामिल रही लेकिन पूर्व जिला कलेक्टर ने इशिता मसानिया पर कार्रवाई करने की बजाय सम्भागीय आयुक्त (कमिश्नर) इंदौर की ओर कार्रवाई की अनुसंशा के लिए भेज कर मामले को रफा-दफा कर दिया। जब से उक्त मामले की फाइल दबी हुई है और अब तक कोई कार्रवाई नही हो पाई है।

सूचना अधिकार में आयुक्त कार्यालय से मांगी गई जानकारी अबतक भी नहीं मिली

आरटीआई कार्यकर्ता श्रवण मालवीय द्वारा पूरे मामले में अब तक हुई जांच सहित संभागीय आयुक्त द्वारा की गई कार्यवाही के प्रमाणिक जानकारी मांगी। लेकिन पहले से सब कुछ मिली भगत कर चुके अधिकारी व बाबू जानकारी देने से बचते रहे और कार्यालय के बाबू ने जादू बताते हुए जानकारी देने के बदले 19 अक्टुम्बर 2022 को आरटीआई कार्यकर्ता को कार्यालय से एक पत्र भेज कर अवगत करवाया जाता है कि, आपके द्वारा मांगी गई जानकारी में तृतीय पक्ष की सहमति नही मिलने का हवाला देकर जानकारी नही दी गईं। जिसकी द्वितीय अपील आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा दिनांक 31 अक्टुम्बर 2022 को आयुक्त इंदौर को ही की गई। क्योकि अपीलीय अधिकारी भी आयुक्त इंदौर ही है। द्वितीय अपील के लिए दो से तीन तारीख लग चुकी हैं लेकिन कोई जानकारी नही दी गई।

आयुक्त कार्यालय से आरटीआई कार्यकर्ता को भेजा गया पत्र जिंसमे तीसरे पक्ष द्वारा जानकारी नही देने का हवाला देकर गुमराह कर जानकारी नही दी गई।

आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा आयुक्त इंदौर को की गई अपील।

सत्तापक्षीय नेता हो सकते हैं शामिल, जानकारी नहीं मांगने का बनाया जा रहा दबाव

साड़ी सप्लाई कांड के पीछे सत्तापक्षीय नेताओ का हाथ होने की संभावनाओ से इनकार नही किया जा सकता। आंगनवाडी में साड़ी सप्लाई के नाम पर सभी विकास खंडों की महिला एवं बाल विकास परियोजना के कार्यालयों पर साड़ी की गठानें भेज दी गई और जो साड़ी स्वेच्छा से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को बाज़ार से खरीदना था वो अधिकारी ने सुपरवाइजर के माध्यम ने सप्लाई करने की योजना बनाई जिसका भांडा पेटलावद विकासखंण्ड में फूट गया। जांच में कार्यवाही के बाद महिला बाल विकास के प्रभारी परियोजना अधिकारी और अपर कलेक्टर अभय खराड़ी का ट्रांसफर तक कर दिया गया। आरटीआई कार्यकर्ता श्रवण मालवीय ने बताया कि, मामले की जानकारी नही दी जा रही है और संभागीय आयुक्त के बाबू गुमराह कर जानकारी नही दे रहे हैं। क्योंकि पूर्व कलेक्टर द्वारा कार्रवाई के लिए अनुशंसा हेतु भेजा प्रकरण अब तक आयुक्त तक नही पहुँचा है। आरटीआई कार्यकर्ता ने बताया, इंदौर से जानकारी मांगने के बाद झाबुआ से सुनील डाबी व्यक्ति का फोन आता है और जानकारी नही मांगने ओर मिल-बैठकर बात करने की बात कही जा रही है।

आखिर कौन और क्यों बचाया जा रहा है इशिता मसानिया को

उक्त मामले में हुई जांच में सुपरवाइजर सहित महिला बाल विकास पेटलावद की परियोजना अधिकारी इशिता मसानिया पर कार्रवाई के लिए अनुशंसा की गई थी लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नही हुई। मतलब साफ है इस मामले में परियोजना अधिकारी इशिता मसानिया को बचाया जा रहा है। राजनीतिक संरक्षण की बात भी सामने आ रही है जिसके चलते अब तक कोई कार्रवाई नही हुई। बाज़ार में चर्चा गर्म है कि, मेडम जी जज बनने की तैयारी कर रही है और उनको किसी कार्रवाई के चलते परेशानी न आये ये देखते हुए मामले को अब तक दबाकर रफा-दफा किया जा रहा है।

भटकता विद्यार्थी जीवनः स्कूलों में काउंसलिंग की आवश्यकता

क्या जन्म देने वाले माता-पिता का अपने बच्चों पर अधिकार नहीं...?

माही की गूंज,खवासा।

माही की गूंज ने एक चिंतन के साथ ''मोबाइल से भटकता विद्यार्थी जीवन'' शीर्षक के साथ 17 नवंबर के अंक में समाचार प्रकाशित किया था।

आज के समय में यह मोबाइल जितना सुविधाजनक है उतना ही दुष्परिणाम ही ला रहा है। वही विद्यार्थी कम उम्र में ही भटक रहे हैं और अपने परिवार की प्रतिष्ठा के साथ स्वयं का भविष्य भी दलदल में ले जा रहे हैं। जन्म देने वाले माता-पिता की कही बातों को भी कम उम्र में यह बच्चे नकारने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यहां यह सवाल उठता है क्या जन्म देने वाले माता-पिता का अधिकार अपने बच्चों पर नहीं है...?

इन्हीं सवालों के साथ कम उम्र में ही विद्यार्थियों के भटकते जीवन को लेकर बड़ी चिंता व चिंतन का विषय बन गया है। जिसके लिए माता-पिता के साथ स्कूली संस्था व इस दिशा में कार्य करने वाले सामाजिक संस्थानों को भी गंभीरता के साथ इस मसले पर एक चिंतन के साथ कार्य करने की आवश्यकता है।

बांग्लादेशी गौतम राय का शराबी पुत्र सुमन की लड़की के परिजनो के हत्थे चढने के बाद हुई पंचायती।

बहला-फुसलाकर ले गया था बंगाली, पर नहीं हुई कोई ज्यादती

हमारे विधिक व्यवस्था अनुसार घटना व घटना के आरोपों व बाद में बयानों के आधार पर अपराध दर्ज एवं धाराए बढ़ती है। आज हम खवासा क्षेत्र के दो मामले के साथ अपनी बात लिख रहे हैं। जिसमें घटना व दर्ज हुए अपराध पर केंद्रित नहीं होकर इस तरह की हो रही घटना पर सामाजिक चिंतन करने की आवश्यकता जरूरी है।

पहला मामला जो कि, वर्तमान में सुर्खियों में है। जिसमें एक जैन समाज की लड़की को बांग्लादेशी गौतम राय का लड़का सुमन ले गया था और मामला यह कि, विवाहित सुमन ने अपनी विवाहिता पत्नी को छोड़ एक नाबालिक लड़की से प्रेम किया और लड़की को ऐसा जाल में फंसाया की जो लड़का कहे वही वह नाबालिक लड़की करने को तैयार हो गई और भरे बाजार में माता-पिता का विरोध कर लड़की उक्त बांग्लादेशी गौतम राय के लड़के विवाहित सुमन के साथ चली गई थी।

चूँकि उक्त मामला जैन समाज की लड़की होने व जिले में पुलिस कप्तान भी जैन ही होने के चलते सुर्खियों में रहा था। तो वहीं पुलिस अधिकारी भी अपने पुलिस कप्तान अगम जैन के सामने जब तक लड़की को लेकर न आ जाए तब तक निगाहें मिलाने में भी संकोच कर रहे थे। वही उक्त मामले को प्रमुखता के साथ माही की गूंज में उजागर होने व एसपी के समक्ष अपनी कार्यक्षमता का परिचय देने के साथ खवासा-थांदला पुलिस ने इनके एक-एक रिश्तेदारों को कब्जे में लिया। जिसमे धार, उज्जैन आदि जिलों से भी 8-10 लोगों को पकड़कर लाए और पूछताछ की। पुलिसया दबाव के साथ ही षड्यंत्रकारी तथा बांग्लादेशी गौतम राय को अपने पुत्र के साथ लड़की को आना ही पड़ा।

15 दिसंबर को विवाहित सुमन व लड़की पेटलावद होते हुए खवासा आ रहे थे, जिसकी सूचना लड़की ने ही उसके पिता परिवार को फोन पर दी। बामनिया में लड़की परिवार के हत्थे धोखेबाज सुमन जिसने पहले ही एक लड़की की जिंदगी शादी करने के साथ छोड़कर खत्म करने का कार्य किया। जिसको लड़की के पिता परिवार ने बामनीया में पकड़ा और सुमन द्वारा मुहजोरी करने पर पंचायती भी भरे बाजार में कर दी। तथा अपनी लड़की को अपने कब्जे में ले लिया और सुमन को पुलिस के हवाले कर दिया। लड़की के दिए अपने बयान में बताया, सुमन ने उसके साथ किसी प्रकार की ज्यादती नहीं की थी, नाबालिक होने के साथ उसे बहला-फुसलाकर सुमन ले गया था और दिन में धार्मिक स्थलों के दर्शन करते और रात में किसी रेलवे स्टेशन पर जा कर रुक जाते थे, कहा।

जिसपर सुमन के विरुद्ध अपराध क्रमांक 775/2022 धारा 363 व 366 में गिरफ्तारी लेकर न्यायालय में सुमन को पेश कर जेल भेजा गया। यहां अगर लड़की के साथ किसी प्रकार की ज्यादती किए जाने संबंधी बयान होते तो लड़के के विरुद्ध धारा 376 भी पंजीबद्ध होता।

एनएचपीएस स्कूल के गेट तक आई छात्रा बिना परीक्षा दिए हुई लापता

वहीं दूसरे मामले में खवासा एनएचपीएस स्कूल की 9वीं की छात्रा उम्र 14 से 15 वर्ष कोटड़ा निवासी डामोर परिवार की लड़की 10 दिसंबर से लापता है। मामला लड़की के पिता राकेश द्वारा थांदला थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई कि, अर्द्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देने हेतु स्वयं अपनी लड़की को स्कूल के बाहर छोड़कर आया। लेकिन लड़की घर पर नहीं आई। पुलिस ने अपनी तत्परता दिखाते हुए जांच में जुट गई और सामने आया कि, यह स्कूली कक्षा 9वी की नाबालिग छात्रा धनपुरा निवासी किसी तानसिंह भाबोर से मोबाइल पर बात करते हुए 10 दिसंबर के पूर्व माता-पिता ने पकड़ा था। माता-पिता ने अपने अधिकार का उपयोग करते हुए बेटी को एक-दो फटकार भी लगाई और लड़के के द्वारा दिया गया मोबाइल भी लड़की के माता-पिता ने अपने कब्जे में लेकर समझाइश दी कि, बेटी समय आने पर तेरी अच्छी जगह शादी भी करेंगे। परंतु अभी तुझे तेरा भविष्य सुधारना है और तेरा ध्यान अभी सिर्फ पढ़ाई पर केंद्रित करना चाहिए के साथ बेटी को समझाया और बेटी ने भी माता-पिता की बात समझ गई ऐसा विश्वास दिलाया। वहीं 10 दिसंबर को पिता स्वयं अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए अपनी बेटी को समझाइष देते हुए अर्द्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देने हेतु खवासा की एनएचपीएस स्कूल ले गए और स्कूल के बाहर छोड़ पिता घर चला गया। लेकिन बेटी को माता-पिता की दी गई समझाईष काम नहीं आई और न ही उनकी डांट-फटकार।

स्कूल की अन्य छात्रा, गेटमैन व प्राचार्य से पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि, उक्त छात्रा 10 दिसंबर को स्कूल के अंदर ही नहीं आई। गेट मैन ने गेट के बाहर उसे देखा और साढे 10 बजे की जैन बस में बैठ थांदला की ओर चली गई। वही आठवीं की छात्रा ने भी बयान दिया कि, बदला हुआ नाम सुनीता गेट के बाहर मिली, पेपर देने हेतु स्कूल के अंदर जाने हेतु कहा तो सुनीता ने पेपर देने से इनकार करने के साथ माता-पिता ने तानसिंह के साथ मोबाइल पर बात करते हुए पकड़ लिया और उसे फटकार लगाने की बात कही। जिस पर आठवीं छात्रा ने सुनीता को समझाया कि, माता-पिता है जो डांट भी सकते हैं व मार भी सकते हैं उन पर गुस्सा करना सही नहीं है। पर सुनीता को यह बात भी समझ नहीं आई और खवासा की ओर से आई जैन बस में बैठकर चली गई लेकिन वह घर नहीं पहुंची।

पुलिस की जांच में प्रथम दृष्टया यह भी सामने आया कि, छात्रा ने किसी अन्य का मोबाइल लेकर बस में तानसिंह को मोबाइल लगाया। पुलिस, तानसिंह को पूछताछ के लिए लाई और सामने आया कि, तानसिंह झाबुआ कॉलेज में बीए सेकंड ईयर कर रहा है और उस लड़की के साथ शादी करूंगा की बात दोहरा रहा है। लेकिन लड़की कहां है यह मुझे नहीं मालूम कह रहा है। पुलिस ने धारा 363 में नामजद अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जांच कर रही है।

पूरा मामला लड़की के सामने आने के बाद ही सामने आएगा। लेकिन उक्त मामले के साथ यह आत्मचिंतन की जरूर आवश्यकता है कि, विद्यार्थी 10- 12 वर्ष की उम्र से ही शारीरिक बदलाव के चलते भटक रहा और कम उम्र में ही अपने भविष्य को खराब कर गलत संगति में जा रहे है। इसलिए माता-पिता के साथ स्कूलों में भी कक्षा 6 से 12वीं तक में बच्चों की बदलती मनोवृत्ती को सही दिशा दिखाने के लिए काउंसलिंग की आवश्यकता है, जिसके लिए स्कूली संस्था, संस्था स्तर पर एक पखवाडे में एक बार बच्चों की काउंसलिंग की जाए। साथ ही 2 से 3 माह में ऐसे काउंसलर भी बुलाये जाए, जो संस्था में आकर भटकते विद्यार्थी जीवन को सही दिशा दिखा सके। वही बाल विकास विभाग को भी इस और ध्यान देने की आवष्यकता है। तय है ऐसा करने पर ऐसे मामलों में कमी जरूर आएगी।

बेसुरी सी जिले में राशन वितरण प्रणाली, गरीबों का हक उन तक पहुंचाने में नाकाम जिला प्रशासन

अपने हक के लिए ग्रामीणों को देने पड़ रहे अधिकारियों के बंगलों व कार्यालयों पर धरने, जनप्रतिनिधियों को भी नहीं है कोई सरोकार, परेशान हो रही आम जनता

माही की गूंज, झाबुआ। मुज्जमील मंसुरी

इन दिनों जिले में राशन वितरण व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई दिखाई पड़ रही है। इसका जीता जागता प्रमाण पिछले लगभग 1 माह में तीन अलग-अलग क्षेत्रों के ग्रामीणों द्वारा अलग-अलग तारीखों में अधिकारियों के कार्यालयों, बंगलों और राशन दुकान पर दिए गए धरने है। ग्रामीणों द्वारा दिए गए यह धरने प्रशासन की कारगुजारियों को भी उजागर कर रहे है। जबकि प्रशासन इस बात को मानने से इंकार कर रहा है कि, उनकी व्यवस्थाओं में खामियां है। प्रशासन के हिसाब से राशन वितरण व्यवस्था पूरी तरह से चॉक चौबंद है। मगर व्यवस्था अगर चॉक चौबंद है तो फिर ग्रामीण यह धरने किस लिए दे रहे है। यह एक यक्ष प्रश्न बन गया है। या तो ग्रामीण झूठ बोल रहे है या प्रशासन उन्हे झुठलाने की कोशिश कर रहा है। जो भी हो लेकिन यह स्पष्ट है कि, राशन वितरण व्यवस्थाओं में कहीं कोई बड़ी चूक तो हो ही रही है। अनाज वितरण व्यवस्था में गड़बड़ी की शिकायतों का अंबार लगा हुआ है लेकिन अधिकारी इसको गंभीरता से ना लेते हुए सिर्फ लीपापोती में लगे हुए है। ऐसे में गरीब ग्रामीणों का सब्र टूटने लगा है। वे एक जुट होकर प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर उतरने को मजबूर हो रहे है। जिले के अधिकतर स्थानों पर अनाज कम मिलने या नहीं मिलने की शिकायतें सामने आ रही है। ग्रामीणों के लिए राशन एक मूलभूत आवश्यकता है और इसका कोई विकल्प नहीं है। खुद मुख्मंत्री इस राशन वितरण में हो रही गड़बड़ी को लेकर सख्ती दिखा रहे है। लेकिन स्थानीय प्रशासन पर इसका कोई असर अब तक देखने को नहीं मिल रहा है। पिछले दिनों चुनावी यात्रा के दौरान मुख्मंत्री से शिकायत होने के बाद खाद्य आपुर्ति अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई हुई थी। तत् समय राशन वितरण व्यवस्था में सुधार होने के आसार नजर आए थे, लेकिन प्रशासन अब पुरानी ढपली पुराना राग वाली स्थिति में आ गया है। पिछले दिनों राशन नहीं मिलने को लेकर 26 नवंबर को ग्राम नवापाड़ा बाटिया के ग्रामीण सैकड़ों की संख्या में राशन दुकान के बाहर पात्रता पर्ची लेकर धरने पर बैठ गए थे। उसके बाद 7 दिसम्बर को ग्राम करड़ावद के सैकड़ों ग्रामीण राशन नहीं मिलने का अरोप लगाते हुए कलेक्टोरेट पहुंचे थे। यहां हर रोज ग्रामीण सुबह 4 बजे से कतार में लगते और शाम 4 बजे तक उनका नंबर नहीं आता। उसके बाद उन्हे यह कहते हुए रवाना कर दिया जाता कि, सर्वर बंद हो चुका है, अब कल ही राशन वितरण हो पाएगा। लगभग एक सप्ताह की फूट-फुटव्वल के बाद ग्रामीणों का सब्र जवाब दे गया और वे सारे राशन कार्ड पोटली में बांधकर झाबुआ कलेक्टोरेट पहुंच गए। इसी तरह का मामला 17 दिसम्बर को भी सामने आया। अब ग्राम ढेकल बड़ीके ग्रामीण सरकारी दुकान से राशन नहीं मिलने से आक्रोशित होकर झाबुआ पहुंचे और कलेक्टर बंगले के गेट पर धरना देकर बैठ गए। लगभग 1 घंटे तक ग्रामीण कलेक्टर बंगले के बाहर धरने पर बैठे रहे लेकिन कलेक्टर मेडम उनसे मिलने बंगले से बाहर नहीं आई। ग्रामीणों का आरोप था कि, उन्हें कम अनाज दिया जा रहा है और एंट्री पूरे चार महीने की हो रही है। विरोध करने पर सेल्समेन डराता धमकाता है। कलेक्टर बंगले के बाहर धरने की खबर सुनते ही बौखलाए अधिकारी हरकत में आए ताबड़तोड़ धरना स्थल पर पहुंचे। काफी जद्दोजहद के बाद अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाया और वहां से कलेक्टोरेट ऑफिस ले गए। ग्रामीणों को सेल्समेन को हटाने का आश्वासन दिया गया तब कहीं जाकर मामला शांत हो पाया। यह सारे मामले पिछले कुछ दिनों के अंतराल में ही हुए है। इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि, जिले में राशन वितरण व्यवस्था की किस तरह से हवा निकली पड़ी है। अधिकारी सिर्फ लीपापोती में ही अपना विश्वास दिखा रहे है। मगर व्यवस्था के सुधार में उनकी कोई रूची दिखाई नहीं पड़ रही है। 17 दिसम्बर को ही एक घटना गेंहू चोरी की सामने आई है। इस घटना में मेघनगर वेयर हाउस से राशन वितरण योजना का गेंहू भरकर एक ट्रक निकला था जिसे झाबुआ के समीप ग्राम करड़ावद में पकड़ा गया। आरोप यह है कि, ट्रक ड्रायवर वाहन से गेंहू की चोरी कर रहा था। चोरी का माल एक ऑटो में भरकर रवाना होना था। मगर उसके पहले ही यह कार्रवाई हो गई। कई लोग बताते है कि, ग्रामीणों की सूचना पर यह कार्रवाई की गई, लेकिन प्रशासन का अपना दावा है कि, एसडीएम द्वारा हाईवे पर गाड़ी रूकी हुई देखी और ऑटो में गेंहू के बोरे देखे तो वाहन चालक से पूछताछ की गई। जिसमें घटना का खुलासा हुआ। बाद में दोनों वाहनों को जप्त कर थाना झाबुआ पहुंचा दिया गया। चोरी की यह घटना इस बात का भी खुला प्रमाण है कि, राशन की इस तरह की चोरी होना आम बात है। यह और बात है कि, इस बार चोर, चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा गया। कुल मिलाकर यह गरीबों के हक का निवाला भ्रष्टाचारियों और चोरों की बदौलत छीना जा रहा है। प्रशासन की नाक के नीचे से गरीबों को मिलने वाले अनाज में गोलमाल हो रहा है, मगर जिम्मेदारों का ढुलमुल रवैया कई सवाल खड़े कर रहा है। कुल मिलाकर बेसुरी सी जिले की राशन वितरण व्यवस्था के कारण गरीबों को उनके हक का राशन जिला प्रशासन उन तक पहुंचाने में नाकाम और नाकारा ही साबित हो रहा है। ग्रामीणों को अपने हक के लिए अधिकारियों के बंगलों व कार्यालयों पर धरने देना पड़ रहे है। जिले के जनप्रतिनिधियों को भी गरीबों के राशन से कोई सरोकार नहीं है, वे अब सिर्फ चुनावी माहौल में वोट लेने के लिए ही पहुंचेगे। जिले के आदिवासी गरीब ग्रामीण यूं ही राशन के लिए परेशान होते रहेंगे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा, संपादक- धर्मेन्द्र पंचाल । मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422